राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रसारीत

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023 (Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार, ०५ मई २०२१ वर्ष-४, अंक -१०१ पृष्ठ-०८ मूल्य-०१ रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सरकार ने केंद्रीय संस्थानों लिखा पत्र- मई में होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करें

नई दिल्ली। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए भारत सरकार के उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने सभी केंद्रीय संस्थानों को पत्र लिखकर कहा है कि मई महीने में होने प्रस्तावित सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। खरे ने केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले संस्थनों के कुलपतियों और डायरेक्टर्स को लिखा, मौजूदा हालात में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी को भी आपके संस्थान में मदद की दरकार तो उसे (छात्र/छात्रा) को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे कि जल्द से जल्द तनाव से बाहर निकल सके। यह भी जरूरी है कि वैक्सीन के लिए योग्य व्यक्तियों को टीका लगवाने को प्रोत्साहित किया जाए और सभी लोग कोविड-19 नियमों को पालन करते हुए सुरक्षित रहें। चूंकि 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए वैक्सीनिशेन अभियान शुरू हो चुका है ऐसे में खरे ने संस्थान प्रमुखों से अपील की कि वे छात्रों को टीकारण अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। मौजूदा हालातों को देखते हुए संस्थानों से कहा गया है कि वे ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखें। जून 2021 में स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कई परीक्षाएं जैसे जेईई, एनईईटी और आईसीएआई व एसएससी, यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाएं भारत में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण स्थगित कर दी गई हैं। वर्तमान में कोरोना के एक्टिव केस 341,3642 हो गए हैं और अब तक कुल 218959 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले:

भाजपा सांसद की धमकी- याद रखना टीएमसी नेताओं और मुख्यमंत्री को भी दिल्ली आना होगा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद सियासी हिंसा शुरू हो गई है। नतीजे वाले दिन ही कोलकाता में BJP के दफ्तर में आग लगा दी गई थी। सोमवार को भी पार्टी के दो कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या की खबर है। इस बीच पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद परवेश साहिब सिंह ने विवादित बयान दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि तृणमूल के नेताओं को भी दिल्ली आना है। उन्होंने कहा कि ॠस्ष्ट के गुंडों ने चुनाव जीतते ही हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मारा। कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ीं। उपद्रवी उनके घरों को आग के हवाले कर रहे हैं। याद रखना ॠस्ष्ट के सांसद , मुख्यमंत्री, विधायकों को भी दिल्ली आना होगा। इसको चेतावनी समझ लेना। चुनाव में हार जीत होती है, मर्डर नहीं। उधर, उत्तराखंड से भाजपा सांसद

अनिल बलूनी ने भी तृणमूल हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, 'तो बंगाल में हिंसा की ये स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। खुद ममता बनर्जी ने मार्च में कह दिया था कि सेंट्रल फोर्स तो चली जाएगी। फिर कौन बचाएगा? उसके बाद तो हम ही होंगे। यानी बंगाल में हिंसा का जो खेल चल रहा है, वो TMC ने पहले ही तय कर रखा था। शर्मनाक!'

भाजपा का आरोप- ममता की शह पर हो रहे हमले

विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने पर गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। दूसरी तरफ, भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले ममता बनर्जी की शह पर हो रहे हैं। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं।

कोविड प्रोटोकॉल के साथ पूरे देश में धरना देंगे भाजपा कार्यकर्ता

भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों के विरोध का फैसला किया है। भाजपा ने कहा है कि 5 मई को पार्टी कार्यकर्ता हर मंडल में इस हिंसा के विरोध में धरना देंगे। इस दौरान कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।

सोमवार को नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपाड़ा में BJP के ऑफिस और कुछ दुकानों पर कुछ लोगों ने हमला कर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान बम भी फेंके गए। एक शख्स ने बताया कि TMC के उपद्रवियों ने मेरी दुकान लूट ली। यहां कम से कम 10 बम फेंके गए हैं। कूचबिहार के सितलकुची से भी हिंसा की खबरें हैं। नंदीग्राम मे BJP के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई।

बंगाल में हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने 5 मई को देशव्यापी धरने का किया ऐलान

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद राज्य में हो रहीं कई हिंसक घटनाओं को लेकर बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी पांच मई को देशव्यापी धरना करने जा रही है। मालूम हो कि बीजेपी का आरोप है कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं, जिसमें कई लोगों की हत्याएं भी की गई हैं। इसके अलावा, सोमवार को भी राज्य में व्यापक पैमाने पर हिंसा देखने को मिली जिसमें कथित तौर पर झड़प और दुकानों को लूटे जाने के दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई तो कई घायल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले की घटना में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी ने एक पार्टी कार्यालय में आगजनी का वीडियो साझा किया है जिसमें बांस की बल्लियां और छत जलती हुई नजर आ रही हैं और परेशान लोगों को चिल्लाते हुए भागते देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर मृत व्यक्तियों की तस्वीरें और एक दुकान से कपड़े लूट कर भागते लोगों की फुटेज वायरल हो रही है। बीजेपी का दावा है कि उसके कम से कम छह कार्यकर्ता और समर्थक हमलों में मारे गए हैं जिनमें एक महिला भी शामिल है। भाजपा इसका आरोप तृणमूल पर लगा रही है। बीजेपी ने पत्रकारों के साथ एक वीडियो साझा किया जिसमें नंदीग्राम में पार्टी दफ्तर में हुई तोड़फोड़ को दिखाया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सीट पर भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थीं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रदेश के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और कोलकाता के पुलिस आयुक्त को तलब कर उन्हें शांति बहाल करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा, सोमवार को भी राज्य में व्यापक पैमाने पर हिंसा देखने को मिली जिसमें कथित तौर पर झड़प और दुकानों को लूटे जाने के दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई तो कई घायल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले की घटना में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।

बेंगलुरु में कोरोना से हो रही इतनी मौतें! श्मशानों के बाहर लगे 'हाउस फुल' के बोर्ड

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के सामने पूरा देश बेबस नजर आ रहा है। हर रोज देश में लाखों कोरोना मामले सामने आ रहे हैं और हजारों लोगों की मौत हो रही हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते इन मामलों के कारण अस्पतालों, मुर्दाघरों और श्मशान पर काम बोझ बढ़ गया है। अस्पतालों में बेड नहीं हैं, मुर्दाघर और श्मशानों में अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं है। कोरोना के कारण हुई मौतों से लाशों का ढेर लग गया है, इसलिए कई श्मशान घाटों में जगह की कमी हो रही है। बता दें कि सोमवार को कर्नाटक में कोरोना के 44,438 नये मामले सामने आए और 239 लोगों की मौत हो गई। ऐसे ही एक मामले में, कर्नाटक के चामराजपेट में एक श्मशान के अधिकारियों ने शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए जगह की कमी के कारण श्मशान के बाहर ÷हाउस फुल÷ का एक साइनबोर्ड लगा दिया। इस श्मशान में लगभग 20 शव दाह संस्कार किए जा सकते हैं, यहां एक बोर्ड लगा दिया और कहा कि दाह संस्कार के लिए और शव नहीं लिए जाएंगे। बेंगलुरु में शहर में 13 शवदाहगृह हैं और कोविड -19 मामलों में हाल ही में वृद्धि के कारण वे सभी भरे हुए चल रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने शहर के श्मशान पर बोझ को कम करने के लिए कोविड -19 मुर्दो को दफन करने के लिए जमीन के रूप में उपयोग करने के लिए बेंगलुरु के आसपास 230 एकड़ जमीन ब्रुहट

बेंगलुरु महानगर पालिक (बीबीएमपी) को आवंटित की है।स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 239 मरीजों की मौत होने से इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16,250 हो गयी है जबकि इस दौरान कोरोना के 44,438 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16 लाख से भी ज्यादा हो गई है। श्मशान की भरी हालत को देखते हुए, सरकार ने परिवार के स्वामित्व वाले खेतों और भूखंडों में दाह संस्कार की अनुमति देने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कर्नाटकमें रविवार को कोरोना के 37,733 ताजा संक्रमणों के बाद 16 लाख का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि 217 से अधिक लोगों की मौत हो गई।

कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, नहीं सुधरे लोग तो अब कंप्लीट लॉकडाउन लगाएंगे

चंडीगढ़। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि यदि लोग नहीं माने तो वह राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन भी लगा सकते हैं। सीएम ने कहा कि वह राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन लोगों ने यदि ढिलाई बंद नहीं की तो फिर उन्हें मजबूरन कंप्लीट लॉकडाउन लगाने पर विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं अब तक राज्य में पूरी तरह से बंदी के खिलाफ रहा हूं क्योंकि इससे गरीब तबके के लोग बुरी तरह से प्रभावित होंगे। इससे इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी और प्रवासी मजदूरों को पलायन करना पड़ेगा। लेकिन संकट नहीं थमा तो फिर कंप्लीट लॉकडाउन के फैसले पर भी विचार करना पड़ सकता है। फिलहाल पंजाब में मिनी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं। इसके अलावा रविवार को कुछ और प्रतिबंधों का ऐलान सरकार की ओर से किया गया था। सोमवार को डीजीपी दिनकर गुप्ता ने सोमवार को बुलाई मीटिंग में कहा कि राज्य में कोरोना प्रतिबंधों को पूरी सख्ती से लागू

मैं अब तक राज्य में पूरी तरह से बंदी के खिलाफ रहा हूं क्योंकि इससे गरीब तबके के लोग बुरी तरह से प्रभावित होंगे। इससे इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी और प्रवासी मजदूरों को पलायन करना पड़ेगा। लेकिन संकट नहीं थमा तो फिर कंप्लीट लॉकडाउन के फैसले पर भी विचार करना पड़ सकता है।

कराने का प्रयास जारी है। इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रेस्तरां से टेक-अवे डिलिवरीज पर भी रोक का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रेस्तरां से सामान लेकर घर जाने की छूट दिए जाने का कुछ युवा बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि घूम सकें। हालांकि रेस्तरां कर्मचारियों की ओर से होम डिलिवरी की परमिशन रहेगी। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स बेचने वाली दुकानों को भी खोलने की छूट दी गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह पंजाब में दूसरे राज्यों की तरह हालात नहीं देखना चाहते, जहां मरीजों को रोड पर ही छोड़ दिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे अपने सीएसआर फंड के जरिए वैक्सीनेशन के अभियान को तेज कर सकें। इसके अलावा उन्होंने मामूली लक्षण वाले लोगों से घरों पर ही इलाज की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की ताकि अस्पतालों पर ज्यादा दबाव न हो सके। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर ने अपनी सरकार की ओर से अस्पतालों की क्षमता को बढ़ाने के उपाय भी गिनाए। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में राज्य में बेडों की संख्या में 20 फीसदी का इजाफा करने का प्रयास किया जाएगा।

5-जी टेस्टिंग की वजह से देश में तबाही मचा रहा कोरोना वायरस?

नई दिल्ली। देश में आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे संदेशों की भरमार है जिनमें कोरोना के लिए 5-जी तकनीक की टेस्टिंग को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि 5 जी टावरों की टेस्टिंग से निकलने वाला रेडिएशन हवा को जहरीला बना रहा है इसलिए लोगों को सांस लेने में मुश्किल आ रही है। साथ ही वायरल पोस्ट में ये भी कहा जा रहा है कि इसी रेडिएशन की वजह से घर में हर जगह करंट लगता रहता है। पोस्ट में सुझाव दिया जा रहा है कि अगर इन टावरों की टेस्टिंग पर रोक लगा दी जाती है तो सब ठीक हो जाएगा। कोरोना

से जुड़े तथ्यों और भ्रमों पर विश्व स्वस्थ्य संगठन की तरफ से जारी रिपोर्ट में इस बात का खंडन किया गया है। 26 मार्च को जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 जी मोबाइल नेटवर्क से कोरोना नहीं फैलता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कोरोना मोबाइल नेटवर्क और रेडियो तरंगों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना उन देशों में भी हो रहा है जहां 5 जी मोबाइल नेटवर्क नहीं है।

यूपी पंचायत चुनाव 2021 : जीत देखने से पहले ही जिंदगी की जंग हार गए 20 उम्मीदवार

गोरखपुर। कोरोना के साये के बीच हुए पंचायत चुनाव के नतीजों पर भी संक्रमण का असर दिखा। प्रदेश में 20 प्रत्याशी ऐसे रहे जो पंचायत चुनाव तो जीत गए लेकिन परिणाम से पहले जिंदगी की जंग हार गए। इनमें सर्वाधिक पांच प्रत्याशी गोरखपुर के और तीन प्रतापगढ़ के रहे। वाराणसी, जौनपुर और अमरोहा के भी 2-2 प्रत्याशी अपनी जीत नहीं देख सके। जबकि सिद्धार्थनगर, देवरिया, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर और आगरा के भी एक एक प्रत्याशी को मौत के बाद विजयी घोषित किया गया। एक दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों की मौत की वजह कोरोना है तो चार दिल दौरा पड़ने से चल बसे। गोरखपुर में एक प्रत्याशी की हत्या कर दी गई थी। गोरखपुर के पिपरौली ब्लाक के मिश्रौलिया गांव के प्रधान प्रत्याशी राघवेन्द्र उर्फ गिलगिल दुबे को चुनाव से एक दिन पहले उनके प्रतिद्वंद्वी शंभू यादव ने गोली मार दी थी। उन्हें केजीएमयू में भर्ती कराया गया था। मतदान के बाद उनकी मौत हो गई। परिणाम राघवेन्द्र के पक्ष में आया। वहीं खोराबार ब्लाक के गहिरा गांव से बीडीसी के प्रत्याशी रंजीत चौबे उर्फ शिप्पू चुनाव जीत गए हैं। चुनाव के बाद रंजीत की कोरोना से मौत हो गई थी। इसी तरह जंगल कौड़िया ब्लाक की ग्राम पंचायत अहिरौली से प्रधान प्रत्याशी इन्द्रा यादव और बड़हलगंज ब्लाक के जैतपुर से प्रधान प्रत्याशी पवन कुमार साहनी भी चुनाव जीत गए हैं। दोनों को कोरोना ने परिणाम आने से पहले निगल लिया। इसी तरह गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल हरपुर में प्रधान प्रत्याशी भुआल यादव की तबीयत मतदान के दिन ही बिगड़ गई थी। इलाज के दौरान दूसरे दिन सुबह उनकी मौत हो गई थी। सोमवार को मतगणना में भुआल भी विजयी घोषित किए गए।

मौत के बाद हुई तीन की जीत

प्रतापगढ़ में तीन प्रत्याशियों की मौत के बाद जीत हुई है। इनमें दो ग्राम प्रधान और एक बीडीसी सदस्य के प्रत्याशी थे।कालाकांकर ग्राम पंचायत की निवर्तमान ग्राम प्रधान मंजू सिंह इस बार भी प्रत्याशी थीं। मतदान के दिन उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में उनकी मौत हो गई। रविवार को मतगणना के बाद उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया। इसी तरह मंगरौरा विकासखंड के मदुरा रानीगंज के निवर्तमान प्रधान व प्रत्याशी रामसुख यादव की एक सप्ताह पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वह भी रविवार को मतगणना में विजयी घोषित किए गए। कालाकांकर में ही केरावडीह की बीडीसी सदस्य प्रत्याशी रफीकुलनिशा को भी मौत के बाद विजयी घोषित किया गया है। रफीकुल की एक सप्ताह पहले मौत हो गई थी।

भारत में अगले दो से तीन महीने तक वैक्सीन का संकट रहेगा

नई दिल्ली। कोरोना माहामारी के बीच वैक्सीन के संकट से जूझ रहे देश में अगले दो से तीन महीने तक स्थिति पटरी पर नहीं लौटने वाली है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि भारत में अगले दो से तीन महीने तक वैक्सीन का संकट रहेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि एक महीने में वैक्सीन की दस करोड़ डोज का उत्पादन जुलाई में ही संभव है। अभी एक माह में औसतन छह से सात करोड़ डोज का उत्पादन हो रहा है। देश छोड़कर लंदन में परिवार संग निवास कर रहे अदार पूनावाला ने ये भी कहा है कि उत्पादन इसलिए नहीं बढ़ाया गया है क्योंकि सरकार से टीके का ऑर्डर नहीं मिला था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस कारण जुलाई तक देश में टीके का संकट बना रह सकता है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारों ने ये नहीं सोचा था कि कोरोना की दूसरी लहर का सबसे अधिक प्रभाव भारत पर पड़ेगा। दूसरी लहर इतनी भयावह होगी इसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी। अधिकतर लोगों ने तो ये मान लिया था कि भारत ने महामारी को पूरी तरह मात दे दी है। इसी कारण प्रति वर्ष औसतन टीके की 100 करोड़ डोज से अधिक के उत्पादन के बारे में नहीं सोचा था।

पूनावाला ने सरकार पर साधा निशाना

पूनावाला ने कहा है कि टीके की 100 करोड़ डोज के ऑर्डर के बाद कोई भी नया ऑर्डर नहीं मिला है। सरकार और अफसरों को कोरोना की दूसरी लहर की बिलकुल भनक नहीं थी। उन्होंने कहा है कि सरकार ने टीके को लेकर नीति बनाई और अब राजनेता वैक्सीन के संकट के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भारत सरकार ने जब टीके के निर्यात पर रोक लगाई तो कंपनी ने दूसरे देशों का पैसा वापस लौटाना शुरू कर दिया है।

● जिम्मेदारों ने ये नहीं सोचा था कि कोरोना की दूसरी लहर का सबसे अधिक प्रभाव भारत पर पड़ेगा। दूसरी लहर इतनी भयावह होगी इसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी। अधिकतर लोगों ने तो ये मान लिया था कि भारत ने महामारी को पूरी तरह मात दे दी है। इसी कारण प्रति वर्ष औसतन टीके की 100 करोड़ डोज से अधिक के उत्पादन के बारे में नहीं सोचा था।

पिछले माह सरकार ने दिए 3 हजार करोड़

अदार पूनावाला ने कहा है कि पिछले महीने सरकार ने टीके का उत्पादन बढ़ाने और एडवांस में ऑर्डर के लिए तीन हजार करोड़ रुपये दिए थे। हमने इसपर काम भी शुरू कर दिया। लेकिन इतनी जल्दी पर्याप्त मात्रा में टीके का उत्पादन संभव नहीं है। मालूम हो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से तैयार कर रहा है। भारत बायोटेक को 1500 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ था।

राज्यों और निजी अस्पतालों को बिक्री

पूनावाला ने कहा है कि अप्रैल तक सरकार ने जितना भी उत्पादन था उसने खरीद लिया। मई से राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को टीका बेचना था। इसी बीच सरकार ने एक मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने का फैसला किया। इसी फैसले के बाद देश में टीके का संकट गहरा गया। यही कारण है कि एक मई को 18.3 लाख लोगों को ही टीका लग सका।

मार्च के बाद से कोई नया ऑर्डर नहीं

टीका बनाने वाली कंपनियों के अधिकारियों की मानें तो सरकार ने मार्च के बाद से कोई नया ऑर्डर नहीं दिया है। इसमें से 80 लाख डोज का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट जबकि बीस लाख डोज का ऑर्डर हैदराबाद के भारत बायोटेक को मिला था। इस ऑर्डर का कुछ हिस्सा मई के मध्य तक केंद्र के निर्देशानुसार राज्यों को मुहैया कराए जाएंगे। इसके बाद सरकार ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है।

संपादकीय

संभलकर लॉकडाउन

कोविड संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए कई विशेषज्ञ सरकार को यह सलाह दे चुके हैं कि वह संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करे। पिछले दिनों अमेरिकी सरकार के मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर एंटनी फौकी ने भी कहा है कि भारत में सरकार को कुछ वक्त के लिए लॉकडाउन लगाकर उस दरमियान अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की तैयारी करनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कहा है कि वे लॉकडाउन लगाने पर विचार करें। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जनता के, खासकर कमजोर वर्गों पर इसके आर्थिक-सामाजिक असर से हम वाकिफ हैं। पहले ही उन्हें सहायता देने की तैयारी की जानी चाहिए।

महामारी को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन एक प्रभावी उपाय है, लेकिन पिछले साल के लॉकडाउन का जो हमारा अनुभव रहा है, उसके मद्देनजर अब सरकारें लंबे वक्त तक पूरा लॉकडाउन करने से हिचकिचा रही हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब देश को संबोधित किया, तो उनके संबोधन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा यही था कि हमें लॉकडाउन से यथासंभव बचना है। पिछले साल लंबे लॉकडाउन की वजह से लोगों के लिए रोजी-रोटी का संकट हो गया, बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर गांवों की ओर लौटने लगे, परिवहन के साधन बंद होने के कारण कई मजदूर हजारों मील पैदल चलकर या तरह-तरह से कष्ट उठाकर लौट पाए। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। एक और संकट यह खड़ा हुआ कि शहरों की घनी बस्तियों में बंद रहे मजदूरों में कोरोना फैलता गया और जब वे लॉकडाउन के बाद अपने गांवों या कस्बों में लौटे, तो वहां कोरोना का विस्फोट हो गया। इसी वजह से अब लॉकडाउन एक डरावना शब्द बन गया है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही ऐसा हुआ, दुनिया के कई देशों में जहां लॉकडाउन का अनुभव इतना कठोर नहीं था, वहां भी लोग लॉकडाउन से आजीज आ गए हैं। यूरोप के कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर आने पर जब लॉकडाउन लगाया गया, तो लोग विरोध में सड़कों पर आ गए। हालांकि, जैसी परिस्थिति अभी भारत में है, उसे देखते हुए पाबंदियां बढ़ाना जरूरी हो गया है। कई राज्यों में अलग-अलग मियाद के लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, हालांकि, कहीं भी वैसी सख्ती नहीं है, जैसी पिछले साल थी। यह खतरा भी है कि पिछले साल भारी आर्थिक नुकसान झेल चुके लोग अब कारोबार बंद होने पर आक्रोशित हो सकते हैं, सरकार भी और आर्थिक नुकसान सहने की स्थिति में नहीं है। अनुभव यह है कि अगर सीमित लॉकडाउन लगाया जाता है, तो वह ज्यादा फायदेमंद होता है अच्छा यही होगा कि राज्य सरकारों को स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर लॉकडाउन का फैसला करने दिया जाए।

लॉकडाउन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के पहले लोगों को राहत देने का इंतजाम करने की सलाह दी है। अगर केंद्र सरकार अभी लोगों को राहत देने का कोई व्यापक कार्यक्रम शुरू करे, तो राज्य सरकारों को लॉकडाउन के उपाय करने में आसानी होगी और लोगों की भी तकलीफें कम होंगी। किसी व्यापक राहत कार्यक्रम से जो आश्वस्ति का माहौल बनेगा, वह इस दौर से निकलने में मददगार हो सकता है।

कड़वी दवा नहीं, सजा दो

कर्नाटक के चामराजनगर में एक अस्पताल में रविवार को ऑक्सीजन संकट के कारण 24 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 23 कोरोना के मरीज थे। दिल्ली, महाराष्ट्र ग्गुजरात, हरियाणा के बाद कर्नाटक भी उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां अस्पतालों के भीतर ऑक्सीजन की कमी या आग लगने के कारण मरीजों की मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक अस्पताल में भी पांच और मध्य प्रदेश के बड़वानी में चार मरीजों की मौत ऐसे ही संकट के चलते हुई है, लेकिन इन मौतों के लिए ऑक्सीजन की कमी को कारण मानने वाला कोई नहीं है। दिल्ली में हर दिन कोई न कोई अस्पताल ऑक्सीजन संकट से निपटने के प्रयास में सर्वोच्च अदालत और उच्च न्यायालय हर सख्ती के उपाय आजमा चुके हैं। सोमवार को भी शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को तीन मई की आधी रात तक ऑक्सीजन संकट दूर करने के हर उपाय करने का आदेश दिया है। और सभी राज्यों से स्पष्ट कहा है कि मरीज किसी भी राज्य का हो उससे आधार कार्ड़ मांगने के बजाए इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए। एक अन्य मामले में चुनाव आयोग की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने उससे मद्रास उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी को कड़वी दवा के तौर पर लेने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि समाज को सही संदेश देने के लिए ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं। याद रहे कि मद्रास उच्च न्यायालय ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके अफसरों पर हत्या का मामला चलाने की चेतावनी दी थी। आयोग का तर्क था कि एक संवैधानिक संस्था होने के नाते उस पर ऐसी टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए, लेकिन आयोग को यह नहीं भूलना चाहिए कि रविवार को जब चेन्नई और कोलकाता में जश्न मनाती जनता को रोकेने के लिए आयोग की चेतावनी का तुरंत असर हुआ, लेकिन रोज अपनों को मरते देखने को विवश जनता अब दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहती है। एक अन्य मामले में सीरम इंस्टीटयूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि उन्हें टीकों के लिए धमकियां दी जा रही हैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर सेना की मदद मांग ली है। ऑक्सीजन और बेड का संकट दूर करने के लिए यह मदद मांगी गई है।

टू दि प्वाइंट/आलोक पुराणिक

किसी दीवार के साए में

कोरोना कोई पहली बार ना हुआ है, शायर मीर (1723-1810) के जमाने में भी हुआ था। उनके कुछ शेरों से उस जमाने में कोरोना के कहर का पता लगता है। मीर का शेर है-

होगा किसी दीवार के साए में पड़ा 'मीर'/क्या रब्त मोहब्बत से उस आराम-तलब को। भावार्थ-इस शेर का मतलब है कि मीर किसी दीवार के साये में एकांत में क्वारंटाइन हुए रहते थे। कहीं आते जाते ना थे। सेहत के लिए बहुत चिंतित रहते थे मीर, इसलिए उन्हें आरामतलब कह दिया गया। पर आरामतलब होकर अगर जान बच रही हो, तो आरामतलबी बुरी बात नहीं है। अपने इस शेर के जरिये मीर क्वारंटाइन होने के महत्त्व को रेखांकित कर रहे हैं। मीर का एक और शेर है- दिखाई दिए यूं कि बे-खुद किया/हमें आप से भी जुदा कर चले।

भावार्थ-मीर एक बार एक कोरोना पॉजिटिव बंदे से टकरा गए। फिर क्या थाग उन्हें हो हो करके घरवालों से घर से ही बाहर कर दिया और कहा कि जाओ अस्पताल में भरती हो जाओ, पंद्रह दिनों तक एकांतवास, क्वारंटाइन होकर आयो। मीर ने इस शेर में अपनी व्यथा कही है कि बताओ वो कोरोना पॉजिटिव क्या दिख गया, हम अपनों से ही जुदा हो गए। कुल मिलाकर मीर कहना चाह रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव से लोगों से छह फुट की दूरी अपनानी चाहिए। दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मीर का एक और शेर है-

सिरहाने 'मीर' के कोई न बोलो/अभी टुक रोते-रोते सो गया है।

भावार्थ-मीर कोरोना के फंदे में आ गए। पुराने शराबी थे, तंबाकू भी जमकर खेंचते थे। मुराद यह है कि फेफड़ों को चौपट करने में मीर आत्मनिर्भर थे, कोरोना पर निर्भर ना थे। फिर कोरोना आ लिया, मीर को सांस लेने में दिक्कत हो गई। ऑक्सीजन का हाल यह था कि सरकार अदालतों से मांगती थी, अदालतें सरकारों से जवाब मांगती थी, सवाल जवाब सब मिल जाते थेग बस ऑक्सीजन ना मिलता था। मीर ऐसे ही एक रात ऑक्सीजन-ऑक्सीजन कहते-कहते रो रोकर सो गएग तो उनके तीमारदारों ने सबसे कहा अभी रोते-रोते सोये हैं, सो कोई मीर के सिरहाने आकर कोई बोले नहीं।

नतीजों से शक्तिशाली हुए क्षत्रप

आरती आर जेरथ

विधानसभा चुनावों के नतीजों को अगर देखें, तो खासतौर पर ममता बनर्जी की जीत स्तब्धकारी है। उन्हें क्या खूब जनादेश मिला है, जब विपक्ष के कद्दावर नेता लगभग रोज ही ममता बनर्जी को निशाना बनाने में लगे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद ममता बनर्जी की सीटों की संख्या घटने के बजाय पिछली बार की तुलना में बढ़ गई है। तमाम विपक्षी नेताओं में अगर आप देखते हैं कि ममता बनर्जी सबसे बड़ी भाजपा विरोधी और प्रधानमंत्री की सबसे मुखर आलोचक रही हैं। ममता बनर्जी ने पूरा चुनाव अभियान नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलाया है। अभियान के दौरान ही उन्होंने सभी विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी थी कि हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए एक नेशनल फ्रंट बनाना चाहिए। आने वाले समय में ममता बनर्जी का यह एक बड़ा एजेंडा होगा कि केंद्र सरकार के विरोध के लिए क्षेत्रीय दलों का एक फ्रंट बनाएं। यह फ्रंट चुनाव के लिए तो नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार सारी शक्तियों का केंद्रीकरण कर रही है, राज्यों को उपेक्षा महसूस हो रही है, इन विषयों पर ममता बनर्जी बाकी पार्टियों को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ खूब लड़ेंगी और इसमें उन्हें तमिलनाडु के द्रमुक नेता एम के स्टालिन और केरल के नेता पी विजयन का साथ मिलेगा। ये दोनों नेता भी अपने-अपने राज्य में बहुत तगड़े जनादेश से जीतकर आए हैं। ये भी संघवाद पर बहुत मजबूती से विश्वास करने वाले नेता हैं।

> ममता बनर्जी के सामने चुनौती अब पहले से बड़ी है। उन्हें केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा बनाने के साथ ही शासन अच्छे से चलाकर दिखाना होगा।

कुल मिलाकर, कोरोना ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी की छवि को धक्का पहुंचाया है और जिस तरह से उनकी देश और विदेश की प्रेस में आलोचना हो रही है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि यह सब पूरा केंद्र सरकार का कुप्रबंधन था, जिसके कारण लोग जान गंवा रहे हैं। अगर सरकार थोड़ा सतर्क रहती और विशेषज्ञों की बात सुन लेती, तो इतना बुरा हाल न होता। अब लड़ाई यहीं से शुरू होगी। आगे आने वाले महीनों में यह बढ़ेगी। विपक्ष का आरोप है कि कोरोना के समय केंद्र सरकार ने वैक्सीन, ऑक्सीजन, लॉकडाउन जैसे फैसलों को पूरी तरह से केंद्रीकृत कर दिया था। पूरा कोरोना प्रबंधन दिल्ली से चल रहा था। आज ज्यादातर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य यही तो बोल रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, दवाओं का अभाव है, ऑक्सीजन की कमी है। महाराष्ट्र तो एक ऐसा राज्य है, जो पहले से ही केंद्र सरकार से लड़ रहा है। अगर आप देखें, तो मुझे लगता है, क्षेत्रीय नेताओं का एक समूह बनेगा, जो चुनौती देगा। मुद्दों के आधार पर चुनौती दी जाएगी और आज सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना महामारी है।

दूसरी ओर, कांग्रेस का तो सफाया हो गया है, कोई भी कांग्रेस की तरफ देख नहीं रहा है। कांग्रेस की अपनी राजनीति है, अपनी सोच है, जो क्षेत्रीय पार्टियों से अलग है। क्षेत्रीय दलों के लिए रास्ता अब आसान हो गया है, कांग्रेस उनकी राह में कोई अड़चन नहीं डाल सकती। अन्य मुख्यमंत्री जैसे ओडिशा में नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी और तेलंगाना में चंद्रशेखर राव अब तक लगभग चुप थे, लेकिन अब कोरोना की वजह से कुछ-कुछ उनकी आवाज भी निकल रही है। ये लोग भी ममता के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। अब देखना है, उत्तर प्रदेश में क्या होता है। छह महीने में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। यहां विपक्षी दलों के पास कानून-व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा कोरोना जिस तरह फैल रहा है, लोग जिस तरह जान गंवा रहे हैं, यह बड़ा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा आंदोलन। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष अगर एकजुट हो गया, तो उसकी आवाज बहुत बढ़ जाएगी। मुख्य बात यही होगी कि क्षेत्रीय पार्टियां केंद्रीकरण का विरोध करेंगी। किसी भी तरह की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाएंगी। मांग उठेगी कि केंद्र सरकार को संघवाद पर आना ही पड़ेगा। हमारा संविधान संघीय ढांचे की गारंटी देता है। चुनावी नतीजों से वन इंडिया, वन पीपुल, वन लंग्वेज के नारे को चोट लगी है। दक्षिण के राज्यों में भाजपा की कोशिशें लगभग नाकाम रही हैं। इन राज्यों में क्षेत्रीय पहचान, भाषा और संस्कृति का महत्व ज्यादा है। यह समझना पड़ेगा कि वन इंडिया का जो सपना है, एक भाषा, एक रहन-सहन रखना, यह नहीं चलेगा। यही आवाज केरल, तमिलनाडु और बंगाल से मुखरता से उठी है। खासकर बंगाल जहां भाजपा ने बहुत जोर लगा दिया, फिर भी लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया।

दूसरी बात, ममता बनर्जी के खिलाफ हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा तो काम नहीं कर सकता, वह तो प्रधानमंत्री हैं। तमिलनाडु में भाजपा के पास क्या चेहरा है? केरल में क्या चेहरा है, श्रीधरन, जो 85 साल के हो चुके हैं? चुनावों ने साफ कर दिया है कि विविधता में एकता का सबक भाजपा को सीखना ही पड़ेगा। हमारे यहां अलग-अलग संस्कृति है, सबको एक धारा में डालना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा हो नहीं सकता। जहां केरल में वामपंथियों की जीत की बात है, तो यह चुनाव वाम ने नहीं जीता है। जीत का पूरा श्रेय विजयन के प्रशासन को जाता है। वहां जीत विचारधारा की नहीं, कामकाज की हुई है। बाढ़ आई थी, कोरोना फैला है, इसे जिस तरह से विजयन ने संभाला है, उसे लोगों ने सराहा है। केरल में एक और महत्वपूर्ण बात हुई है कि ईसाई वोट वामपंथियों को गया है। यह वोट हमेशा कांग्रेस की ओर जाता था। इस समुदाय ने भी बेहतर प्रशासन देखकर ही विजयन के पक्ष में वोट किया है। उधर, तमिलनाडु में कमल हासन जैसे अभिनेता चुनाव हार गए हैं। लगता है, तमिलनाडु में फिल्म स्टार की राजनीति का जमाना खत्म हो गया, अब नई राजनीति चलेगी। देखने वाली बात होगी कि स्टालिन के समय किस तरह की राजनीति शुरू होती है। स्टालिन पुरानी द्रविड़ मुद्रा में नहीं हैं। तमिलनाडु में जो हुआ है, वह अपेक्षित ही था, दस साल से अन्नाद्रमुक शासन में थी। जयललिता भी मैदान में नहीं थीं, स्टालिन को फायदा हुआ। बहरहाल, लोगों का ज्यादा ध्यान बंगाल पर लगा रहेगा। जहां ममता बनर्जी के सामने हिंसा का मामला होगा और 'कट मनी' का भी। दोनों कमियों को किसी तरह से संभालना पड़ेगा। भाजपा अब बड़ी विपक्षी है, तीन से 75 सीट पर आ गई है, लेफ्ट और कांग्रेस साफ है। ममता बनर्जी के सामने चुनौती अब पहले से बड़ी है। उन्हें केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा बनाने के साथ ही शासन अच्छे से चलाकर दिखाना होगा।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

कोरोना के बीच चुनाव

चुनाव आयोग की जवाबदेही का प्रश्न

अनूप भटनागर

वैश्विक महामारी कोविड-19 के बीच ही पश्चिम बंगाल सहित चार राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग की भूमिका और उसकी कार्यशैली की तीखी आलोचना हो रही है। चुनाव के दौरान कोविड-19 के तांडव से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मद्रास उच्च न्यायालय ने इन चुनावों के दौरान हुयी मौतों पर टिप्पणी भी कर दी कि इसके लिये निर्वाचन आयोग पर हत्या के आरोप में मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन क्यों और कैसे, इस बारे में उच्च न्यायालय खामोश रहा।

संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत देश में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्यों का प्रशासन तंत्र और पुलिस व्यवस्था भी आयोग के नियंत्रण में ही रहती है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अथवा निरंकुशता के मामले में आयोग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

लेकिन सवाल यह उठता है कि कोविड महामारी के दौरान चार राज्यों व एक केंद्रशासित प्रदेश की विधानसभा के चुनाव कराने के अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन के बीच अगर कोई समस्या पैदा होती है तो आयोग के पास क्या विकल्प हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी के निधन की स्थिति में उस सीट पर चुनाव स्थगित किया जा सकता है, लेकिन क्या कोरोना जैसी महामारी के दौरान समूची राज्य विधानसभा का चुनाव एक निर्धारित अवधि से आगे स्थगित किया जा सकता है। क्या आयोग के लिये कई चरणों में चुनाव के कार्यक्रम को अचानक ही एक तारीख पर कराना संभव होगा? क्या इसके लिये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रोग्रामिंग और प्रत्याशियों के नाम आदि में बदलाव की आवश्यकता नहीं होती।

कोरोना महामारी से उत्पन्न गंभीर स्थिति के मद्देनजर पिछले साल बिहार विधानसभा के चुनाव रद्द कराने के लिये उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गयी थी। याचिका में राज्य के कोरोना मुक्त होने तक चुनाव स्थगित करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन न्यायालय ने इसे खारिज करते हुये कहा था कि कोरोना चुनाव स्थगित करने का कोई आधार नहीं हो सकता।

संविधान के अनुच्छेद 174 के अंतर्गत किसी भी राज्य विधानसभा के कार्यकाल के अंतिम सत्र के बाद छह महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है, हालांकि यह अनिवार्यता विधानसभा भंग किये जाने के मामलों में लागू नहीं होती है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुड्डुचेरी और असम विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के तथ्य के मद्देनजर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। आयोग ने साथ ही संविधान में प्रदत्त अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुये चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों के पालन के निर्देश भी जारी किये थे। इसके बावजूद, इन चुनावों में यह देखा गया कि व्यापक अधिकार प्राप्त होने के बाद भी आयोग कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों को लागू कराने में असफल रहा। जनसभाओं में नेताओं और प्रत्याशियों के साथ ही लोगों के चेहरे से मास्क नदारद थे और इसमें सामाजिक दूरी का पालन करना तो दूर की बात थी।

निर्वाचन आयोग ने पिछले साल ही बिहार विधानसभा के साथ ही म.प्र. विधानसभा की 28 सीटों के लिये उपचुनाव के लिये कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी किये थे। इन दिशा-निर्देशों के बावजूद म.प्र. में प्रत्याशी और राजनीतिक दल अपनी सभाओं में इनका पालन नहीं कर रहे थे।

इन्हीं तथ्यों को देखते हुये म.प्र. उच्च न्यायालय ने अक्तूबर, 2020 इन चुनावी सभाओं पर रोक लगाते हुये कहा था कि इनका आयोजन उस समय तक नहीं होगा जब तक जिलाधिकारी और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित नहीं कर दे कि वर्चुअल चुनाव प्रचार संभव नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि जनसभा की अनुमति मिलने पर राजनीतिक दलों को सभी में अपेक्षित लोगों की दुगनी संख्या की सुरक्षा के लिये मास्क और सैनिटाइजर आदि खरीदने के लिये जिलाधिकारी के पास धन जमा कराना होगा।

इस आदेश के खिलाफ निर्वाचन आयोग ही उच्चतम न्यायालय गया था जहां शीर्ष अदालत ने 26 अक्तूबर, 2020 को इस आदेश पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि यह सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि उसके दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन हो और ऐसा नहीं होने पर उचित कार्रवाई की जाये।

ऐसा नहीं है कि निर्वाचन आयोग ने ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं की। संभवत- हाल के कुछ दशकों में पहली बार आयोग पर पक्षपात करने और गैर-भाजपाई दलों की शिकायतों पर निष्पक्षता से कार्रवाई नहीं करने के गंभीर आरोप लगे हैं।

उम्मीद है कि इन चुनावों के दौरान हुई तीखी आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुये निर्वाचन आयोग भविष्य में विधानसभा चुनाव के दौरान पहले से ज्यादा सावधानी बरतेगा और उसके निर्देशों का पालन नहीं करने वालों से ज्यादा सख्ती से निपटेगा।

मुद्दा

सांसों पर भारी कालाबाजारी

डॉ. संजय वर्मा

आपदा में अवसर के मुहावरे को सही अर्थों में किसी ने आत्मसात कर चरितार्थ किया है, तो वे हैं देश और समाज के कलंक- कालाबाजारी। नर्स, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर चलाने वाले दुकानदार से लेकर परचून वाले और रेहड़ी पर फल-सब्जी आदि बेचने वालों की पूरी फौज है, जो कोरोना की दूसरी लहर से ज्यादा तेज और संक्रामक ढंग से देश के हर इलाके में घुसपैठ कर चुकी है। कोई दो-चार हजार के रेमडेसिविर इंजेक्शन को अस्पतालों से चोरी कर 20 से 70-80 हजार रुपये तक में बेच रहा है, उसके लिए असली होने की कोई गारंटी नहीं है।

ऑक्सीजन सिलेंडर तो बहुतेरे कालाबाजारियों के लिए सात पीढ़ियों के खाने-पीने का इंतजाम करने वाला उपकरण बन गया है। अस्पतालों में बिस्तर से लेकर दवा और ऑक्सीजन तक की किल्लत से आजिज तीमारदारों की प्राथमिकता अपने मरीजों की जान बचाना है। ऐसे में वे खून के घूंट पीकर भी जिंदगी भर की कमाई एक झटके में कालाबाजारियों के हाथों सुपुर्द करने की विवशता झेल रहे हैं। सवाल है कि कालाबाजारी का यह खेल शुरू कहां से होता है? कोरोना महामारी के एक साल से ज्यादा समय में उम्मीद थी कि सरकार अपने स्वास्थ्य तंत्र को इतना मजबूत कर लेगा कि अगर यह बीमारी किसी के पास पहुंची भी, तो छू कर निकल जाएगी, लेकिन चुनावी रैलियों, जलसों, कुंभ मेले और मतगणना को प्राथमिकता देने वाली सरकारों के निकम्मेपन ने आखिर वह मौका ला दिया है कि जब यह महामारी आम लोगों को छूने के बाद बेखौफ निगलने लगी है। यह न होता, अगर सरकारी व्यवस्था के नाम पर अस्पतालों में सिर्फ एक फोल्डिंगग बिछावन और मामूली दवाओं से आगे बढ़कर कोरोना का मुकम्मल इलाज और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती, लेकिन संकट तो इससे भी बुरा है। कोरोना से बीमार को इलाज मिलना तो दूर, अस्पतालों में एक अदद बिस्तर मिलना भी आकाश कुसुम सरीखा हो गया है। दिल्ली और एनसीआर के कोरोना मरीजों को अस्पताल में दाखिला नहीं मिलने का नतीजा है कि तीमारदार उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर चंडीगढ़ और उत्तराखंड के चंपावत तक ले जाने को मजबूर हुए हैं। जहां हॉस्पिटल बेड की गारंटी तो मिलती है, पर इलाज से पहले वहां पहुंचने की देरी भारी पड़ जाती है। इस विवशता का बर्बर फायदा कालाबाजारियों ने उठाया है। कोरोना की दूसरी लहर के ताजा दौर में अभी तक शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो, जब इंसानियत को शर्मसार करते दर्जनों लोग जीवनरक्षक दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर मुंहमांगी कीमत पर बेचते और उनमें से एकाध पकड़ में आते नजर न आए हों। यही नहींग जो होम्योपैथिक-आयुर्वेदिक दवा और आंवले-पपीते जैसी फल-सब्जी सोशल मीडिया पर शरीर में प्रतिरोधक क्षमता और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में कारगर बताई जाती हैग उसकी कीमतों में भी आग लग गई है।

ऑक्सीजन का स्तर नापने वाला सस्ता का उपकरण ऑक्सीमीटर अब तो केमेस्टि शॉप ही नहीं, ई कॉमर्स वेबसाइटों पर भी तीन से चार गुना कीमत पर बेचा जा रहा है। बेशक, मानवता के दुश्मन इस आपदा में कमाई का मौका देख रहे हैं, लेकिन सवाल उस तंत्र का है, जिसके जिम्मे इस कृत्रिम अभाव के रचनाकारों और कालाबाजारियों पर नजर रखना और उनकी धरपकड़ करना है। कहने को इस पूरे किस्से की रोकथाम के लिए कानून मौजूद है। कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूतत का रखरखाव निवारण अधिनियम, 1980 की धारा-3 के तहत जरूरी चीजों की आपूतत में बाधक बन रहे व्यक्ति को 6 महीने की हिरासत में रखा जा सकता है।

इसी तरह आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियमग 1955 में चीजों के भंडारण की सीमा और मूल्य की सीमा तथा उत्पादन में बढ़ोत्तरी व दुकानदारों के खातों की जांच जैसी गतिविधियां शामिल हैं। ईसी अधिनियम में कालाबाजारी के दोषी को 7 साल की सजा या जुर्माना या दोनों तरह के दंड का प्रावधान है। इन कानूनों के तहत छिटपुट कार्रवाई भी हुई है। जैसे हाल में, 27 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में ऐसे 62 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। साथ ही दवाओं की जमाखोरी करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) और गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा करने की बात कही जा चुकी है, लेकिन कालाबाजार के फायदों के आगे ये कार्रवाइयां नाकाफी हैं। इससे साबित होता है कि बेशुमार फायदे के आगे ऐसे कानूनी जोखिम नगण्य साबित हो रहे हैं। लिहाजा इन उपायों से आगे बढ़कर कुछ नजीरी मिसालें सरकार और प्रशासन को कायम करनी होंगी। मरीजों को अस्पताल में सहजता से बिस्तर, दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा तो कालाबाजार अपनी मौत मर जाएगा।

महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने 'ऑक्सीजन ऑन व्हील्स' की पेशकश की, उत्पादकों को अस्पतालों से जोड़ा

मुंबई, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने मंगलवार 'ऑक्सीजन ऑन व्हील्स' (ओ2डब्ल्यू) की पेशकश की, जो उत्पादकों को अस्पतालों तथा चिकित्सा केंद्रों के साथ जोड़कर ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक मुफ्त सेवा है। कंपनी ने एक बयान में बताया कि इस सेवा की शुरुआत महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़, चाकन, नासिक और नागपुर जैसे शहरों में की गई है। इसके तहत लगभग 100 वाहनों की तैनाती की जा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि यह सेवा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स द्वारा प्रशासन और स्थानीय निकायों के साथ मिलकर संचालित की जाएगी। कंपनी ने यह भी कहा कि वह सिविल सोसाइटी और सरकारी विभागों के साथ दिल्ली सहित अन्य शहरों में भी इस सेवा का विस्तार करने के लिए बातचीत कर रही है। इसके अलावा मरीजों के घरों में सीधे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की पहल के विस्तार पर भी विचार किया जा रहा है। भाषा पाण्डेय पाण्डेय 0405 1336 मुंबई जसजस आवश्यक .मुंबई अर्थ 10 वायरस महिंद्रा ऑक्सीजन महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने 'ऑक्सीजन ऑन व्हील्स' की पेशकश की, उत्पादकों को अस्पतालों से जोड़ा मुंबई, चार मई (भाषा) महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने मंगलवार 'ऑक्सीजन ऑन व्हील्स' (ओ2डब्ल्यू) की पेशकश की, जो उत्पादकों को अस्पतालों तथा चिकित्सा केंद्रों के साथ जोड़कर ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक मुफ्त सेवा है। कंपनी ने एक बयान में बताया कि इस सेवा की शुरुआत महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़, चाकन, नासिक और नागपुर जैसे शहरों में की गई है। इसके तहत लगभग 100 वाहनों की तैनाती की जा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि यह सेवा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स द्वारा प्रशासन और स्थानीय निकायों के साथ मिलकर संचालित की जाएगी। कंपनी ने यह भी कहा कि वह सिविल सोसाइटी और सरकारी विभागों के साथ दिल्ली सहित अन्य शहरों में भी इस सेवा का विस्तार करने के लिए बातचीत कर रही है। इसके अलावा मरीजों के घरों में सीधे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की पहल के विस्तार पर भी विचार किया जा रहा है।

कोरोना की दूसरी लहर पर बोले रघुराम राजन, दूरदर्शिता और नेतृत्व की कमी सामने आई

बिजनेस डेस्कः भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। पिछले कई दिनों से देश में 3 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज हो रहे हैं। भारत ने 4 लाख नए संक्रमण मामलों का भी रिकॉर्ड बनाया है। मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और एरोजाना 350,000 से ऊपर नए मामले आ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि संक्रमण में तेजी से %नेतृत्व और दूरदर्शिता की कमी% सामने आई है। ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में राजन ने कहा कि पिछले साल की पहली वेव के बाद दोबारा संक्रमण में तेजी आना दिखाता है कि लोग संतुष्ट होकर बैठ गए थे। राजन ने कहा, ÷अगर आप सावधान होते, अगर आप चौकन्ने होते, तो आपको समझना चाहिए था कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है।÷ राजन ने कहा, ÷अगर कोई इस बात पर ध्यान दे रहा है कि दुनियाभर में क्या हो रहा है, जैसे कि ब्राजील का उदाहरण देखिए, तो उसे समझना चाहिए कि वायरस लौटकर आता है और संभावित रूप से ज्यादा संक्रामक रूप में।

भारत ने पर्याप्त वैक्सीन नहीं बनाई

राजन ने ब्लूमबर्ग से कहा, ÷पिछले साल मामलों में कमी आने के बाद ऐसा समझा गया कि हमने सबसे बुरा दौर देख लिया है और हम इससे निकल गए है और अब इकनॉमी खोली चाहिए। इसी संतुष्टता से हमें नुकसान हुआ। पहली वेव के खिलाफ थोड़ी सफलता की वजह से ही शायद भारत ने अपनी जनसंख्या के लिए पर्याप्त वैक्सीन नहीं बनाई। हो सकता है सोचा गया हो कि अभी समय है कि हम वायरस से निपट चुके हैं और वैक्सीनेशन धीरे-धीरे शुरू कर सकते हैं।

लॉकडाउन की वजह से Goldman Sachs ने भारत के वृद्धि अनुमानों को घटाया

बिजनेस डेस्क:

अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप और उसके चलते कई राज्यों तथा शहरों में लागू लॉकडाउन के मद्देनजर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को 11.7 प्रतिशत से घटाकर 11.1 प्रतिशत कर दिया। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर भयानक रूप ले चुकी है और इस बीमारी से अब तक 2.22 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हर दिन संक्रमण के 3.5 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। इस कारण पूरे देश में सख्त लॉकडाउन की मांग भी जोर पकड़ने लगी है, हालांकि आर्थिक नुकसान को देखते हुए मोदी सरकार ने अभी तक इस कदम से परहेज किया है। गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट में कहा, लॉकडाउन की तीव्रता पिछले साल के मुकाबले कम है। फिर भी, भारत के प्रमुख शहरों में सख्त प्रतिबंधों का असर साफ दिखाई दे रहा है। शहरों में सख्त लॉकडाउन से सेवाओं पर खासतौर से असर पड़ा है। इसके अलावा बिजली की खपत और अप्रैल में विनिर्माण पीएमआई के स्थिर रहने से विनिर्माण क्षेत्र पर असर पड़ने के संकेत भी मिल रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने कहा, कुल

मिलाकर, अधिकांश संकेतक अभी भी बता रहे हैं कि पिछले साल दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) के मुकाबले इस बार असर कम पड़ा है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि हालांकि तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में तेजी वापस लौटने की उम्मीद है, क्योंकि तब प्रतिबंध कुछ हद तक कम हो सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि ऐसे हालात में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि दर 11.1 प्रतिशत रह सकती है, जबकि पहले इसके 11.7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया था।

ओला इलेक्ट्रिक ने वेन बर्गेस को वाहन डिजाइन का प्रमुख नियुक्त किया

नयी दिल्ली,

ओला इलेक्ट्रिक ने मंगलवार को कहा कि उसने वेन बर्गेस को वाहन डिजाइन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी, जो इस साल जुलाई में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को बाजार में पेश करने के लिए तैयार है, ने कहा कि बर्गेस कंपनी के पूरे उत्पाद रेंज के लिए वाहन डिजाइन की अगुवाई करेंगे, जिसमें स्कूटर, बाइक, कार और बहुत कुछ शामिल होगा। एक बयान में कहा गया है कि बर्गेस ने अपने शुरुआती करियर में रोल्स रॉयस और बेंटले से लेकर एस्टन मार्टिन और जगुआर लैंडरोवर के साथ काम किया है और उनके पास वाहन डिजाइन का लगभग तीन दशक का अनुभव है। कंपनी ने बताया कि वह जगुआर एफ-टाइप स्पोर्ट्स कार के मुख्य डिजाइनर थे, और फिर जगुआर एफ-पेस एसयूवी के लिए स्टूडियो निर्देशक रहे। ओला के अध्यक्ष और समूह के सीईओ भाविश अग्रवाल ने कहा कि नेतृत्वकारी टीम में बर्गेस का जुड़ना एक शानदार कदम है और यह कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहनों में वैश्विक अपील और सौंदर्य को लाएगा।

कोरोना का असरः भारत से यात्रा को लेकर अमेरिकी प्रतिबंध लागू, सिर्फ इनको मिलेगी छूट

बिजनेस डेस्कः अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कोविड-19 महामारी के सबसे बुरे दौर का सामना कर रहे भारत से आने वाले लोगों के लिए घोषित यात्रा प्रतिबंध मंगलवार से प्रभावी हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने शुक्रवार को एक घोषणा पत्र जारी कर पिछले 14 दिन से भारत में रह रहे उन लोगों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो अमेरिकी नागरिक नहीं हैं। भारत में कोविड-19 के प्रकोप के चलते ऐसा किया गया। अमेरिका ने अपने नागरिकों, ग्रीन कार्ड धारकों, उनके गैर अमेरिकी जीवनसाथियों तथा 21 साल से कम आयु के बच्चों समेत विभिन्न वर्गों को इस यात्रा प्रतिबंध से छूट दी है। ये यात्रा प्रतिबंध अनिश्चितकाल के लिए लागू किए गए हैं और इस संबंध में राष्ट्रपति के अगले घोषणा पत्र से ही ये समाप्त हो सकते हैं। यह फैसला स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के तहत रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) की सलाह पर किया गया है। इस यात्रा प्रतिबंध से छात्रों, शिक्षाविदों और पत्रकारों समेत विभिन्न वर्गों के लोगों को छूट दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने घोषणा पत्र जारी होने के बाद बताया कि छात्रों, शिक्षाविदों, पत्रकारों और कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण प्रभावित देशों में बुनियादी ढांचे संबंधी अहम सहयोग मुहैया कराने वाले लोगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

भारत की कोविड से लड़ाई में मदद के लिए आगे आई सैमसंग, देगी 50 लाख डॉलर

बिजनेस डेस्क:

इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता उपकरण बनाने वाली कोरियाई कंपनी सैमसंग ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ भारत की लड़ाई में योगदान देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को 50 लाख डॉलर अर्थात 37 करोड़ रुपए की सहायता एवं अस्पतालों के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के साथ हेल्थकेयर सेक्टर को समर्थन देने की घोषणा की है। कंपनी ने आज कहा कि यह निर्णय भारत में विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने और स्थानीय प्रशासन की तत्काल आवश्यकता का आकलन करने के बाद लिया गया है। सैमसंग केंद्र सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु को 30 लाख डॉलर का दान देगी। इसके अलावा, हेल्थकेयर सिस्टम की मदद के लिए सैमसंग 20 लाख डॉलर की चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराएगी, जिसमें 100 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, 3,000 ऑक्सीजन सिलेंडर और दस लाख एलडीसी सिरिंज शामिल हैं। ये सामग्री उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को उपलब्ध कराई जाएगी। एलडीएस या लो डेड स्पेस सिरिंज इंजेक्शन के बाद डिवाइस में बचने वाली दवा की मात्रा को न्यूनतम बनाती है, जिससे वैक्सीन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होता है। मौजूदा सिरिंज में उपयोग के बाद बहुत अधिक मात्रा में दवा रह जाती है और बर्बाद होती है। नई टेक्नोलॉजी ने 20 प्रतिशत तक अधिक दक्षता का प्रदर्शन किया है। यदि मौजूदा सिरिंज से 10 लाख खुराक दिए जाते हैं, वहीं एलडीएस सिरिंज वैक्सीन की समान मात्रा के साथ 12 लाख खुराक दे सकती है। सैमसंग ने इन सिरिंज के विनिर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने के लिए मदद प्रदान की है। अपनी नागरिक पहल के हिस्से के रूप में, सैमसंग भारत में अपने 50,000 से अधिक पात्र कर्मचारियों और लाभार्थियों को टीकाकरण खर्च को वहन करेगी। इसमें सभी सैमसंग एक्सपीरियंस कंसल्टैंट्स, जो पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिस रिटेल स्टोर्स पर काम करते हैं, शामिल होंगे।

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उत्पादन अधारित प्रोत्साहन योजना को लेकर दिशानिर्देश जारी किए

नई दिल्ली:

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने उद्योग की 10,900 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के लिए दिशानिर्देश जारी किया है। क्षेत्र की वृद्धि के लिए इस योजना की घोषणा हाल ही में की गई है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के लिए %ऑनलाइन पोर्टल% की शुरूआत की। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपए के व्यवव आवंटन के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना नाम से एक नई केंद्रीय योजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद वैश्विक स्तर पर अग्रणी खाद्य विनिर्माण कंपनियां तैयार करने में मदद करना तथा खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय बाजार में आगे बढ़ाना है। मंत्रालय ने तीन श्रेणियों के आवेदकों से इस योजना के अंतर्गत विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों को शुरू करने के लिए बिक्री आधारित प्रोत्साहन और अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथत 17 जून है। पहली श्रेणी में, आवेदक बड़ी संस्थाएं हैं जो बिक्री और निवेश मानदंडों के आधार पर प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदक विदेशों में भी ब्रांडिंग व विपणन गतिविधियां शुरू कर सकते हैं और एक सामान्य आवेदन के साथ योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी श्रेणी के तहत नवोन्मेषी और जैविक उत्पाद बनाने वाले एसएमई आवेदक बिक्री के आधार पर पीएलआई प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरी श्रेणी में विदेशों में ब्रांडिंग व

विपणन गतिविधियां शुरू करने के लिए केवल अनुदान के लिए आवेदन किया जा सकता है। योजना के तहत बिक्री आधारित प्रोत्साहन 2021-22 से 2026-27 तक यानी छह साल के लिये आधार वर्ष के मुकाबले बढ़ी हुई बिक्री पर दिया जाएगा। बढ़ी हुई बिक्री की गणना के लिए आधार वर्ष पहले 4 वर्षों के लिए 2019-20 होगा। पांचवें और छठे साल के लिये यह क्रमश- 2021-22 और 2022-23 होगा।

रेमडेसिवीर का उत्पादन बढ़कर प्रतिमाह 1.05 करोड़ शीशी हुआः मंडाविया

नयी दिल्ली,

केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को कहा कि देश में रेमडेसिवीर का उत्पादन लगभग तीन गुना बढ़कर प्रतिमाह 1.05 करोड़ हो गया है और सरकार इस एंटीवायरल दवा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। मंडाविया ने एक ट्वीट में कहा कि दवा की उत्पादन क्षमता चार मई को प्रतिमाह 1.05 करोड़ शीशी को पार कर गई, जो इस साल 12 अप्रैल को 37 लाख शीशी थी। इस तरह उत्पादन क्षमता में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि एक महीने पहले 20 संयंत्रों की तुलना में इस समय देश के 57 संयंत्रों में इस एंटीवायरल दवा का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ''जल्द ही, हम बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे।'' मंडाविया ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सरकार कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। देश में कोविड संक्रमण में भारी बढ़ोतरी के बीच रेमडेसिवीर की मांग भी कई गुना बढ़ गई है।

मुंबई में आवास पंजीकरण अप्रैल में 42% गिरकर 10,136 इकाई रहा

मुंबई:

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रकोप और स्टांप ड्यूटी शुल्क में कमी की अवधि समाप्त हो जाने से पिछले महीने के मुकाबले अप्रैल में आवासीय संपत्तियों का पंजीकरण 42 प्रतिशत गिरकर 10,136 इकाई रह गया। नाइट फ्रैंक इंडिया ने बताया यह गिरावट और भी अधिक होती क्योंकि 90 प्रतिशत खरीदारों ने आवासीय संपत्तियों पर कम स्टाम्प ड्यूटी का लाभ उठाने के लिए एक अप्रैल से पहले ही स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने दरअसल कोरोना महामारी के बीच आवास की मांग को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक स्टांप शुल्क को दो से तीन प्रतिशत घटा दिया था। राज्य सरकार ने इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी भरने के बाद संपत्ति पंजीकरण की अवधि को चार महीने के लिए बढ़ाने की भी घोषणा की थी। नाइट फ्रैंक ने बताया कि मुंबई के चर्चगेट से दहिसर और कोलाबा से मुलुंद क्षेत्र में अप्रैल 2021 में 10,000 आवासीय संपत्ति पंजीकरण दर्ज किया जबकि मार्च में पंजीकरण की यह संख्या 17,449 इकाई की थी। हालांकि इसमें यह भी पाया गया कि इसमें केवल सात प्रतिशत पंजीकरण अप्रैल के दौरान नई आवासीय बिक्री का रहा वहीं शेष 93 प्रतिशत पंजीकरण दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच हस्तांतरित संपत्तियों से रहा। नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, ''आवासीय संपत्ति क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों के दौरान स्टांप शुल्क कम होने के कारण एक स्वस्थ उछाल दर्ज किया गया। हालांकि, स्टंप ड्यूटी शुल्क राज्य सरकार के खजाने में बहुत योगदान देता है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस कदम से अचल संपत्ति सेक्टर को थोड़ी मजबूती मिली। इस कदम ने रोजगार और आर्थिक स्थिरता भी प्रदान की। उन्होंने कहा, ''स्टांप शुल्क को घटाना शानदार निर्णय था जिससे कोरोना महामारी के बीच इस सेक्टर और राज्य की अर्थव्यवस्था चलती रही। राज्य सरकार ने अप्रैल में स्टांप ड्यूटी पर घटाए गए शुल्क को वापस लेने का निर्णय किया और इसी दौरान कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भी आ गई। जिससे नए घरों की मांग और बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई है।

IDBI बैंक को 5 साल बाद वित्त वर्ष 2020-21 में 1,359 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ

मुंबई:

एलआईसी नियंत्रित आईडीबीआई बैंक ने सोमवार को बताया कि बीते वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही में उसका एकल शुद्ध लाभ 4 गुना बढ़कर 512 करोड़ रुपए हो गया। बैंक ने पिछले साल इसी तिमाही में 135 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया था। कंपनी ने यह प्रदर्शन अपनी शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) में 38 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि के आधार पर किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में उसका एनआईआई बढ़कर 3,240 करोड़ रुपए हो गया। बैंक ने साथ ही वार्षिक आधार पर 5 साल बाद मुनाफा अर्जित किया। उसने मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,359 करोड़ रुपए का शुद्ध एकल मुनाफा कमाया। इसके उलट वित्तीय वर्ष 2019-20 में बैंक को 12,887 करोड़ रुपए का शुद्ध नुकसान हुआ था। आईडीबीआई बैंक के अनुसार पांच साल बाद बैंक ने मुनाफा अर्जित किया है। आईडीबीआई बैंक ने एक विज्ञप्ति में बताया कि बीते वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही में उसके शुद्ध मुनाफे में करीब चार गुना तेजी आई और उसने 512 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया। बैंक ने पिछले साल इसी तिमाही में 135 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया था। हालांकि, आईडीबीआई बैंक की पूरे साल की आय पिछले साल की तुलना में कम हो गई। पिछले वित्तीय वर्ष में उसकी आय 24,557 करोड़ रुपए

थी, जो उससे पूर्व के वर्ष (2019-20) में 25,295 करोड़ रुपए थी। बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ राकेश शर्मा ने कहा, ÷बैंक पांच साल के नुकसान के बाद (वित्तीय वर्ष 2020-21 में) वार्षिक मुनाफा अर्जित करने में सफल रहा।

कोरोना का असरः Swiggy ने कर्मचारियों को दी राहत, हफ्ते में करेंगे 4 दिन काम

बिजनेस डेस्क:

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए **Swiggy** ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी फर्म स्विगी ने घोषणा की है कि मई में उसके स्टाफ को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही देश की प्रमुख फूड डिलीवरी एप ने अपने स्टाफ को यह भी सुविधा दी है कि वह हफ्ते में किन चार दिनों में काम करना चाहते हैं, इसका भी चुनाव वे खुद कर सकते हैं। स्विगी के एचआर हेड, गिरीश मेनन ने कर्मचारियों को भेजी एक ईमेल में यह जानकारी दी है। गिरीश मेनन ने अपने स्टाफ को लिखे एक ईमेल में कहा, स्विगी के स्टाफ ने काफी मेहनत की है और हम उनका सम्मान करते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए हमने मई में अपने स्टाफ के लिए 4 दिन का कामकाजी हफ्ता **(four-day work week)** रखने का फैसला किया है।÷ इस मेल में लिखा, ÷जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एक कोविड टास्क फोर्स **(covid task force)** बनाया है। हम और अधिक लोगों को इसमें शामिल कर बेहतर काम कर सकते हैं। अगर आप अपने ब्रेक के दिनों में कोविड टास्क फ़ोर्स में सेवा देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कंपनी ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस हिसाब से अपने स्टाफ को राहत पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। स्विगी ने कहा है कि शारीरिक और मानसिक रूप से अपने स्टाफ का ध्यान रखने की जिम्मेदारियों के तहत उसने यह फैसला किया है।

कोविड संकट के दौर में मदद

फूड डिलीवरी करने वाली देश की बड़ी कंपनी ने महामारी सपोर्ट मशीनरी और इमरजेंसी सपोर्ट टीम भी बनाई है। यह संकट के दौर में स्विगी के स्टाफ की मदद कर सकती है।

इसके लिए एक एप डेवलप किया गया है जिसका नाम स्विगी शील्ड एप है। इसके साथ इम्पलॉई सपोर्ट के लिए एक हॉटलाइन भी शुरू किया गया है। कोविड19 सपोर्ट इंफास्ट्रक्चर की मदद से कंपनी के स्टाफ अस्पताल के आईसीयू बेड, प्लाज्मा और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एंबुलेंस सपोर्ट आदि की भी मदद ले सकते हैं।

फूड डिलीवरी कंपनी ने इस तरह की इमरजेंसी सेवा के लिए अपने पार्टनर के नेटवर्क, स्वयंसेवक और हेल्थकेयर कंपनियों से साझेदारी की है।

गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 450 अंक से ज्यादा टूटा

बिजनेस डेस्कः रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ही बैंकिंग, वित्त और स्वास्थ्य क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से बीएसई के सेंसेक्स में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गई। शेयर बाजारों में शुरुआती तेजी रही, लेकिन दोपहर बाद बिकवाली तेज हो गई। इससे सेंसेक्स 465.01 अंक यानी 0.95 प्रतिशत लुढ़ककर 23 अप्रैल के बाद के निचले स्तर 48,253.51 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 137.65 अंक यानी 0.94 फीसदी की गिरावट के साथ 14,496.50 अंक पर बंद हुआ। यह इसका भी 26 अप्रैल के बाद का निचला स्तर है। सेंसेक्स की 30 में से 21 कंपनियों में गिरावट रही। इंडस्ट्रीज का शेयर 2.18 प्रतिशत और डॉ. रेड्डीज लैब का 2.26 प्रतिशत टूट गया।

सनफार्मा में 1.99 प्रतिशत, एचडीएफसी बैंक में 1.74 प्रतिशत, एचडीएफसी में 1.73 प्रतिशत, इंफोसिस में 1.65 प्रतिशत और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.61 प्रतिशत की गिरावट रही। भारती एयरटेल, टाइटन, मारुति सुजुकी और पा?वरग्रिड के शेयर भी एक से डेढ़ फीसदी के बीच टूटे। ओएनजीसी में 1.86 प्रतिशत और बजाज फिनसर्व में 1.12 प्रतिशत की तेजी रही। मझौली और छोटी कंपनियों में बिकवाली कम हुई। बीएसई का मिडकैप 0.50 प्रतिशत लुढ़ककर 20,220.07 अंक पर और स्मॉलकैप 0.57 अंक फिसलकर 21,885.69 अंक पर आ गया। स्वास्थ्य, दूरसंचार, उर्जा और आटो समूहों पर अधिक दबाव रहा। सेंसेक्स 163.11 अंक की मजबूती के साथ 48,881.63 अंक पर खुला और कुछ ही देर में 48,996.53 अंक पर पहुंच गया। दोपहर बाद बाजार में बिकवाली बढ़ने से इसका ग्राफ तेजी से नीचे की ओर लुढ़का और 48,149.45 अंक तक उतरा गया।

अंत में सेंसेक्स सोमवार के मुकाबले 0.95 प्रतिशत नीचे 48,253.51 अंक पर बंद हुआ। बीएसई में कुल 3,141 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ। इनमें 1,585 के शेयरों में गिरावट और 1,383 में बढ़त रही जबकि 173 कंपनियों के शेयर दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद अंततः अपरिवर्तित बंद हुए। निफ्टी भी 53.10 अंक की तेजी के साथ 14,687.25 अंक पर खुला। इसका दिवस का उच्चतम स्तर 14,273.40 अंक और निचला स्तर 14,461.50 अंक दर्ज किया गया।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आईपीएल 2021: बीसीसीआई का बड़ा फैसला, कोरोना के कहर के बीच स्थगित हुआ आईपीएल

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच आईपीएल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आईपीएल को इस सत्र के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि कल कोलकाता नाइट राइडर्स के दो खिलाड़ियों के कोरोना वायरस संक्रमित पाये जाने के बाद से लगातार कई और टीमों के खिलाड़ी संक्रमित पाए गए हैं।

कई टीम खेलने के लिए तैयार नहीं हो रही है। खिलाड़ियों में डर है। ऐसे में बीसीसीआई की ओर से आईपीएल को इस सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि आईपीएल को इस सत्र के लिए स्थगित किया जा रहा है।

कोविड के खिलाफ लड़ाई में फ्रेंचाइजी और हितधारक एकजुट, आईपीएल निलंबन का समर्थन किया

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी और हितधारकों ने मंगलवार को टूर्नामेंट को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के फैसले की सराहना की और जोर देते हुए कहा कि देश जब कोविड-19 के अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है तो क्रिकेट इंतजार कर सकता है। पिछले कुछ दिनों में जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के बीच कोविड-19 के कई मामले सामने आने के बाद बीसीसीआई को आईपीएल को स्थगित करने को बाध्य होना पड़ा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने बयान में कहा, ''इस सब में हम सभी एकजुट हैं। विवो आईपीएल 2021 में सभी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम टूर्नामेंट को स्थगित करने के बीसीसीआई के फैसले का समर्थन करते हैं।'' फ्रेंचाइजी ने कहा, ''रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बीसीसीआई के साथ सलाह मशविरे से काम करके सुनिश्चित करेग कि सभी सुरक्षित घर वापस लौटें।'' पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन ने भी टूर्नामेंट को स्थगित करने के लिए बीसीसीआई की सराहना की। अजहरूद्दीन ने लिखा, ''भारत में कोविड संकट और खिलाड़ियों के पॉजिटिव नतीजों को देखते हुए बीसीसीआई और आईपीएल संचालन परिषद ने आईपीएल को तुरंत प्रभाव से स्थगित करने का सही फैसला किया है।''

इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज और अब कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे केविन पीटरसन ने कहा कि भारत को संघर्ष करते हुए देखना दिल तोड़ने वाला है। पीटरसन ने ट्वीट किया, ''भारत- ऐसे देश को संघर्ष करते हुए देखना दिल तोड़ने वाला है जिससे मैं इतना प्यार करता हूं। आप इससे उबर जाओगे। आप इससे मजबूत बनकर उभरोगे। इस संकट के समय में भी आपकी दयालुपन और उदारता की अनदेखी नहीं होगी।'' आस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य मेंटर डेविड हसी ने ट्विटर के जरिए कहा कि वह टूट चुके हैं जबकि दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने संक्रमित लोगों के जल्द उबरने की कामना की। स्टेन ने ट्वीट किया, ''कोविड किसी की परवाह नहीं करता। यह किसी को पसंद नहीं करता। बीमार जल्द इससे उबरें और उम्मीद करता हूं कि बाकी लोग भी सुरक्षित घर लौटें और स्वस्थ रहें।'' आईपीएल का संचालन सुचारू रूप से हो रहा था लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के दो खिलाड़ियों वरूण चक्रवर्ती और संदीप वारियर के पॉजिटिव पाए जाने के बाद सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ उसका मैच स्थगित करना पड़ा। उसी दिन चेन्नई सुपरकिंग्स के तीन गैर खिलाड़ी सदस्य गेंदबाजी कोच एल बालाजी, सीईओ काशी विश्वनाथन और एक बस क्लीनर पॉजिटिव पाए गए। मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर अमित मिश्रा भी इस वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए जिसके बाद बीसीसीआई ने तुरंत प्रभाव से टूर्नामेंट को स्थगित करने का फैसला किया। सुपरकिंग्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, ''इस मौके पर हम सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों, राज्य संघों, खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और प्रायोजकों का समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम जल्द ही एक बार फिर गरजेंगे।''

गत चैंपियन मुंबई इंडियन्स और पंजाब किंग्स ने घोषणा की कि वे अपने सभी सदस्यों की सुरक्षित वापसी के लिए बीसीसीआई के साथ काम करेंगे। मुंबई इंडियन्स ने ट्वीट किया, ''विवो आईपीएल 2021 के निलंबन के साथ मुंबई इंडियन्स बीसीसीआई और संबंधित अधिकारियों के साथ काम करेगा जिससे कि फ्रेंचाइजी के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके। '' पंजाब किंग्स ने ट्वीट किया, ''पंजाब किंग्स बीसीसीआई और अन्य अधिकारियों के साथ काम करेगा जिससे कि टीम के सभी सदस्यों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित हो।'' सनराइजर्स ने भी स्वास्थ्यकर्मियों का आभार जताते हुए ट्वीट किया, ''एक साथ मिलकर हम स्थिति से लड़ेंगे और सुरक्षित तथा मजबूत बनकर उभरेंगे।'' पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली ने भी सभी से जरूरी एहतियात बरतने की अपील की।

आईपीएल बायो बबल छोड़कर मालदीव पहुंचे माइकल स्लैटर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरीसन पर जताई थी नारजगी

मेलबर्न। (एजेंसी)।

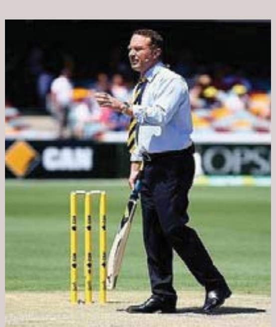

क्रिकेटर से कमेंटेटर बने माइकल स्लैटर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के जैव सुरक्षित वातावरण (बायो बबल) को छोड़कर मालदीव चले गये हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण वहां से उड़ानों को 15 मई तक निलंबित कर रखा है। 'द आस्ट्रेलियन' समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार स्लैटर मालदीव चले गये हैं क्योंकि आस्ट्रेलियाई सरकार के स्पष्ट किया है कि आईपीएल में हिस्सा ले रहे आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और अन्य को स्वदेश लौटने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। मालदीव पहुंचने से पहले स्लैटर ने ट्विटर पर आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरीसन को भारत से अपने देशवासियों को स्वदेश वापसी की अनुमति नहीं देने के लिये आड़े हाथों लेते हुए इसे अपमानजनक बताया था।

स्लैटर ने ट्वीट किया था, ''यदि हमारी सरकार को आस्ट्रेलियाई नागरिकों की सुरक्षा की परवाह है तो वह हमें स्वदेश लौटने की अनुमति देगी। यह अपमानजनक है। किसी भी अनहोनी के लिये आप जिम्मेदार होंगे प्रधानमंत्री। हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने का आपने साहस कैसा किया। आप कैसे पृथकवास प्रणाली को सुलझाते हैं। मुझे आईपीएल में काम करने के लिये सरकार ने अनुमति दी थी और अब सरकार नजरअंदाज कर रही है। '' मॉरीसन ने स्लैटर की टिप्पणी को 'बेतुका' करार दिया। उन्होंने 'नाइन नेटवर्क' से कहा, ''यह पूरी तरह से बेतुका है।

ऐसा अधिक से अधिक लोगों की सुरक्षित घर वापसी और आस्ट्रेलिया को तीसरी लहर से बचाने के लिये किया गया है। '' मॉरीसन ने कहा, ''प्रत्येक प्रणाली को कुछ जटिलताओं का सामना करना पड़ता है और मैं यह प्रणाली नहीं तोड़ने वाला हूं। मैं जो करने जा रहा हूं और वह इस प्रणाली की सुरक्षा के लिये उचित कार्रवाई है ताकि मैं अधिक आस्ट्रेलियाई लोगों को सुरक्षित घर पहुंचा सकूं और आस्ट्रेलियाई जनता को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाऊं। '' आस्ट्रेलिया ने भारत में कोविड-19 के प्रकोप के कारण वहां से व्यावसायिक उड़ानों को प्रतिबंधित कर रखा है जिससे आईपीएल में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और कमेंटेटरों की समस्या बढ़ गयी है। आस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने देश के नागरिकों के भारत से आने पर अस्थायी रोक लगा रखी है। यदि वे अपने आगमन से पहले 14 दिन के अंदर भारत में रहते हैं तो सरकार ने उनके लिये पांच साल जेल की सजा या भारी जुर्माने की चेतावनी दी है।

आईपीएल 2021 स्थगित होने के बाद यूएई में आयोजित किया जा सकता है टी-20 विश्व कप

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

इस साल भारत में होने वाला टी-20 विश्व कप यूएई में आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को लगता है कि कोई भी टीम उस समय यहां आने में सहज महसूस नहीं करेगी। इस बारे में अंतिम फैसला एक महीने में कर दिया जाएगा, लेकिन पता चला है कि जैव सुरक्षित वातावरण(बायो बबल) में कोविड-19 के कुछ मामले पाए जाने के कारण इंडियन प्रीमियर लीग(आईपीएल) स्थगित किए जाने के बाद बीसीसीआई भी अक्टूबर-नवंबर में होने वाले 16 टीमों के टूर्नामेंट को आयोजित करने से कतरा रहा है।

पीटीआई को पता चला है कि बीसीसीआई के अधिकारियों की हाल में केंद्र सरकार के कुछ शीर्ष अधिकारियों से चर्चा हुई तथा टूर्नामेंट को यूएई में आयोजित करने पर काफी हद तक सहमति बन गई है। यह टूर्नामेंट नौ स्थानों पर खेला जाना है जिनकी घोषणा अभी नहीं की गई है। बीसीसीआई के सूत्रों ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, 'आईपीएल का चार सप्ताह के अंदर निलंबन इस बात का संकेत है कि देश पिछले 70 सालों में अपने सबसे बुरे स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है, तब इस तरह की ग्लोबल प्रतियोगिता की मेजबानी करना वास्तव में सुरक्षित नहीं होगा।' उन्होंने कहा, 'भारत में नवंबर में (कोविड-19 की) तीसरी लहर आने की संभावना है। इसलिए बीसीसीआई मेजबान रहेगा लेकिन टूर्नामेंट संभवत- यूएई में आयोजित किया जाएगा।'

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सितंबर में भारत में तीसरी लहर की चेतावनी दी है। भारत में अभी स्थिति विकट बनी हुई है तथा पिछले कुछ समय से हर दिन तीन लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, जिससे अधिकतर क्रिकेट बोर्ड चिंतित हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल(आईसीसी) ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल क्रिकेट टीमों की सुरक्षा को लेकर जोखिम नहीं उठाएगा। एक अन्य सूत्र ने कहा, 'आप यह तय मान लीजिए कि यदि स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तो अगले छह महीने तक कोई भी देश भारत का दौरा नहीं करना चाहेगा।'

इसमें कहा गया कि, 'यदि एक और लहर आती है तो खिलाड़ी और उनके परिजन बेहद सतर्क रहेंगे। इसलिए उम्मीद है कि बीसीसीआई टूर्नामेंट का आयोजन यूएई में करने पर सहमत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आईपीएल के निलंबन के बाद बीसीसीआई के अधिकारी किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। जून में आईसीसी की बैठक होनी है जिसमें अंतिम फैसला किया जाएगा, लेकिन आईपीएल को स्थगित किए जाने के बाद भारत में टूर्नामेंट के आयोजन की संभावना न के बराबर है।'

आईपीएल टूर्नामेंट में बने रहना चाहते हैं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर,सीए ने किया ऐलान

मेलबर्न। (एजेंसी)।

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स संघ (एसीए) के प्रमुख ने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दो खिलाड़ियों के कोविड-19 के लिये पॉजिटिव पाये जाने के बावजूद आस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अपनी संबंधित फ्रेंचाइजी टीमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने के लिये इस टी20 टूर्नामेंट में बने रहना चाहते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वारियर को इस खतरनाक वायरस के लिये पॉजिटिव पाया गया है। इससे उनका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ सोमवार को होने वाला मैच स्थगित कर दिया गया।

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के गेंदबाजी कोच एल बालाजी के पॉजिटिव आने के बाद सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच बुधवार को होने वाला मैच भी स्थगित कर दिया गया। लेकिन एसीए प्रमुख टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा कि उनके देश के क्रिकेटरों की अभी आईपीएल छोड़ने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने हालांकि कहा कि टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद उनकी स्वदेश वापसी को लेकर चिंता बढ़ गयी है। ग्रीनबर्ग ने रेडियो 2जीबी से कहा, ''मुझे लगता है कि अधिकतर खिलाड़ी अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने के लिये तैयार है। वे परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ होने के बाद वहां गये थे। ''

उन्होंने कहा, ''वे टूर्नामेंट को समाप्त होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन वे इसके समाप्त होने के बाद स्वदेश लौटना चाहते हैं और यह चिंता का विषय है क्योंकि इसको लेकर कोई निश्चित योजना नहीं है कि तब यह कैसे होगा। '' ग्रीनबर्ग ने कहा कि केकेआर की टीम में शामिल आस्ट्रेलियाईखिलाड़ी पैट कमिन्स और बेन कटिंग ठीक हैं और पृथकवास में अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। उन्होंने इसके साथ ही उम्मीद जतायी कि आईपीएल में आगे कोविड-19 के पॉजिटिव मामले नहीं आएंगे।

बीसीसीआई ने 4 भारतीय महिला खिलाड़ियों को 'हंड्रेड' में खेलने की अनुमति दी

नयी दिल्ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने टी20 कप्तान हरमनप्रीत कौर सहित चार महिला क्रिकेटरों को जुलाई में ब्रिटेन में होने वाले पहले 'हंड्रेड' टूर्नामेंट में खेलने के लिये अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी कर दिया है। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा भी उन चार खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें 100 गेंद के टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति दी गयी है। चौथी खिलाड़ी के नाम का पता अभी नहीं चला है। बीसीसीआई सूत्रों ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, ''हरमनप्रीत, मंधाना, दीप्ति और एक अन्य खिलाड़ी को मंजूरी दे दी गयी है। बीसीसीआई ने उन्हें एनओसी दे दी है।'' पता चला है कि ये चारों खिलाड़ी जून-जुलाई में इंग्लैंड दौरे के बाद ब्रिटेन में ही रहेंगी। भारतीय दौरे की शुरुआत 16 जून को एकमात्र टेस्ट मैच से होगी। यह दौरा 15 जुलाई को तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय के साथ समाप्त होगा। इस बीच तीन मैचों की वनडे श्रृंखला भी खेली जाएगी। इस दौरे के लिये भारतीय टीम का चयन अभी तक नहीं किया गया है जबकि बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति जल्द ही मुख्य कोच की घोषणा कर सकती है। चयनित खिलाड़ियों को 27 मई को रिपोर्ट करनी होगी लेकिन अभी यह पता नहीं चला है कि वे ब्रिटेन का दौरा कैसे करेंगे क्योंकि कोविड-19 मामलों के बढ़ने के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारत से उड़ानों को निलंबित कर रखा है। सूत्रों ने कहा, ''खिलाड़ियों को दौरे के लिये 27 मई को रिपोर्ट करने को कहा गया है। '' हरमनप्रीत, मंधाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स ने 2019 में किया सुपर लीग में हिस्सा लिया था। महिलाओं के हंड्रेड के लिये इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इस टूर्नामेंट को बाद में भंग कर दिया था।

कोरोना की वजह से आईपीएल 2021 हुआ सस्पेंड तो पाक फैन्स करने लग गए जमकर ट्रोल

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

पिछले लगभग एक महीने से आईपीएल 2021 के मैचों का आनंद लेने वाले फैन्स के लिए बुरी खबर है, क्योंकि बीसीसीआई ने लीग में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद सोमवार को इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल (आईपीएल जीसी) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मिलकर यह फैसला लिया। टूर्नामेंट स्थगित होने से पाकिस्तान के फैन्स को बीसीसीआई और भारतीय फैन्स को ट्रोल करने का मौका मिल गया और उन्होंने इसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स बनाए।

गौरतलब है कि सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद केकेआर और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के बीच मैच को स्थगित करना पड़ा था। ऐसी खबरें आ रही थीं कि आईपीएल के बचे हुए सभी मैच मुंबई में कराए जाएंगे, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के ऋद्धिमान साहा के कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद आईपीएल को फिलहाल सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। लीग के चेयरमैन बृजेश पटेल ने कहा कि हम अगले उपलब्ध समय में इस प्रतियोगिता का आयोजन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस महीने ऐसी संभावना नहीं है। वहीं बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, 'हम देखेंगे कि क्या साल के दौरान बाद में हमें आईपीएल आयोजन के लिए कोई उपयुक्त समय मिल सकता है। यह सितंबर हो सकता है लेकिन अभी यह केवल कयास होंगे।

भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के कार्यकारी निदेशक आर के सचेटी का कोविड से निधन

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

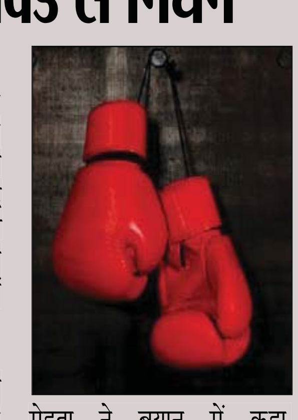

भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के कार्यकारी निदेशक आर के सचेटी का कोविड-19 से जूझने के बाद मंगलवार को निधन हो गया। वह 56 वर्ष के थे। यह कुशल खेल प्रशासक पिछले कुछ समय से यहां एक अस्पताल में वेंटीलेटर पर थे। बीएफआई ने बयान में कहा, ''बेहद दुख के साथ हम आपको सूचित कर रहे हैं कि आर के सचेटी, कार्यकारी निदेशक (बीएफआई) आज सुबह हम सबको छोड़कर अनंत यात्रा पर चले गये जिससे खेल जगत में बड़ा शून्य पैदा हो गया। '' भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने भी सचेटी के निधन पर शोक व्यक्त किया। आईओए महासचिव राजीव मेहता ने बयान में कहा, ''आईओए के संयुक्त सचिव, बीएफआई के कार्यकारी निदेशक और प्रिय मित्र राजकुमार सचेटी के असामयिक निधन की खबर से बहुत दुखी हूं। '' भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने भी इस खेल प्रशासक के निधन पर शोक जताया।

आईपीएल अध्यक्ष बोले, विदेशी खिलाड़ियों को वापस भेजने का तरीका ढूंढ लेंगे

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के चेयरमैन बृजेश पटेल ने मंगलवार को कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) जैविक रूप से सुरक्षित वातावरण में कोविड-19 संक्रमण के मामले सामने आने पर लीग को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद विदेशी खिलाड़ियों की वापसी का तरीका ढूंढ लेगा।

सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के अनुभवी स्पिनर अमित मिश्रा के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद लीग को निलंबित करने की घोषणा की गई। विदेशी खिलाड़ी कैसे वापस जाएंगे इस बारे में पूछे जाने पर बृजेश ने कहा कि हमें उन्हें स्वदेश भेजने की जरूरत है और हम ऐसा करने का तरीका ढूंढ लेंगे।

इस लुभावनी लीग से जुड़े विदेशी खिलाड़ी अपने देशों में लौटने को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि भारत में घातक महामारी फैलने के कारण कई देशों ने यात्रा पाबंदियां लगाई हैं। बीसीसीआई इससे पहले भी विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षित वापसी का आश्वासन दे चुका है। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने कहा था कि उनके देश के क्रिकेटरों को उसकी चार्टर्ड विमान में यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं है, जो भारत, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आईपीएल के बाद ब्रिटेन ले जाएगा।

भारत और न्यूजीलैंड को 18 जून से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है और उन्हें आईपीएल खत्म होने के बाद इंग्लैंड रवाना होना था। सोमवार को चेन्नई सुपरकिंग्स के गेंदबाजी कोच एल. बालाजी के अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज संदीप वारियर और वरुण चक्रवर्ती भी पॉजिटिव पाए गए थे।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

मददगार सितारे

श्वेता बसु प्रसाद सत्यजीत रे की जन्मशताब्दी पर बनाई अपनी पेंटिंग कर रहीं नीलाम

कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए देंगी पैसा

श्वेता ने सोशल मीडिया पर पेंटिंग की नीलामी के बारे में बताया है। नीलामी 60 हजार रुपए से शुरू की है। श्वेता लिखती हैं– पेंटिंग ऑन सेल फॉर कोविड फंड्स, एक्रिलिक ऑन कैनवास। मैं एक खुद से सीखी हुई पेंटर हूं। कृपया मेरे प्रयास को देखें। मैं एक कलाकार हूं। मैं घर पर बैठकर लोगों की मदद करने का और कोई रास्ता नहीं जानती, जबकि मैं वाकई मदद करना चाहती हूं। हैप्पी बर्थडे रे।

3 दिन तक ओपन रहेगी बिडिंग – गौरतलब है कि फिल्म इंडस्ट्रीज में सत्यजीत रे का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। 2 मई को उनके जन्म के सौ साल पूरे हो गए हैं। श्वेता ने लिखा– सत्यजीत रे ने कहानियां लिखीं और आम आदमी के बारे में फिल्में बनाई, यह सही है कि मैं आज उनकी जन्म शताब्दी पर यह पहल कर रही हूं। श्वेता ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा है कि यह नीलामी 3 दिन तक ओपन रहेगी।

पेंटिंग के लम्हे भी शेयर किए

श्वेता ने इस पेंटिंग को बनाने के लम्हे भी शेयर किए हैं। जिसमें वे पेंटिंग बनाते हुए दिखाई दे रही हैं। श्वेता ने लिखा है कि इस पेंटिंग का कॉपीराइट रिजर्व है। श्वेता ने इसमें सत्यजीत रे की ऑस्कर ट्रॉफी और कैमरे के साथ उनके लिखे अमर किरदार भी दिखाए हैं। श्वेता ने इसे 2 मई के दिन ही तैयार किया है। बात अगर श्वेता के फिल्मी कॅरियर की करें तो वे मकड़ी, मकबूल, द ताशकंद फाइल्स जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।

कोविड पॉजिटिव हिना ने पिता को खोने के बाद इमोशनल होकर लिखा-

मैं वो लाचार बेटी हूं जो मां के साथ भी नहीं रह सकती

कोरोना की दूसरी लहर जहां एक तरफ पूरे देश के लिए भयानक साबित हुई है वहीं हिना खान के लिए ये दुख पिता के गुजरने और खुद कोरोना पॉजिटिव होने से दोगुना हो चुका है। एक्ट्रेस के पिता का निधन 20 अप्रैल को हार्ट अटैक से हो हुआ था जिसके बाद एक्ट्रेस खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। रिपोर्ट आने के बाद से ही हिना अपनी मां से दूर अकेले क्वारैंटाइन हो चुकी हैं। इस मुश्किल समय में मां से दूर रहने पर एक्ट्रेस ने इमोशनल होकर एक नोट शेयर किया है। हिना खान ने सोशल मीडिया पर अपने क्वारैंटाइन मूमेंट की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, एक लाचार बेटी, जो अपनी मां को सहारा देने के लिए उनके साथ भी नहीं रह सकती, जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, ये समय बहुत कठिन है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आसपास के हर व्यक्ति के लिए। लेकिन कहा जाता है, बुरा वक्त ज्यादा समय तक नहीं रहता, लेकिन हिम्मत वाले लोग हमेशा रहते हैं, और मैं हमेशा से अपने पिता की स्ट्रॉन्ग गर्ल थी, हूं और हमेशा रहूंगी। अपनी दुआ भेजते रहिए प्लीज।

सोशल मीडिया से बनाई दूरी

एक्ट्रेस ने हाल ही में फैंस को जानकारी देते हुए बताया कि वो और उनका पूरी परिवार पिता के गुजर जाने के शोक में डूबा हुआ है, ऐसे में वो सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं। अब से उनके सभी सोशल मीडिया हैंडल उनकी टीम द्वारा अपडेट किए जाएंगे।

महामारी में मददगार सितारे

अब फरहान अख्तर ने कोरोना पीड़ितों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ

एक्सल प्रोडक्शन के जरिए कई एनजीओ को दिया डोनेशन

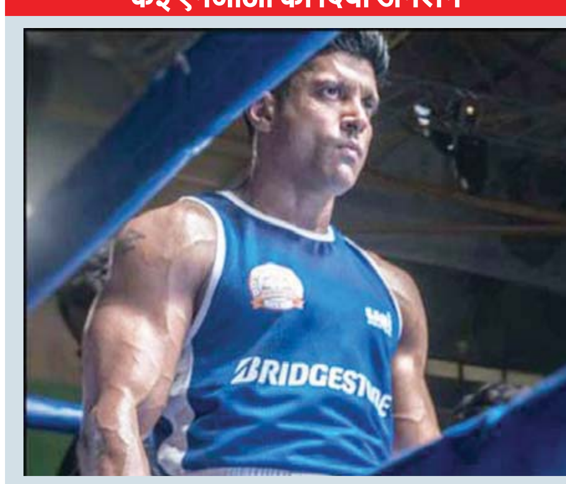

देश में कोविड 19 की दूसरी लहर आते ही लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लगातार पीड़ितों को ऑक्सीजन, दवाइयों और जरूरी सामान की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस मुश्किल समय में अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स अपना योगदान दे रहे हैं जिनमें अब फरहान अख्तर का नाम भी जुड़ चुका है। फरहान ने हाल ही में अपने प्रोडक्शन एक्सल मूवीज के जरिए कई एनजीओ को डोनेशन दिया है जो ग्राउंड लेवल पर लोगों को ऑक्सीजन और खाना मुहैया करवा रहे हैं। इन एनजीओ की जानकारी भी एक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। डोनेशन के बाद फरहान ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा, उन ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट शेयर कर रहा हूं जिन्हें अब तक एक्सल मूवीज ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए डोनेशन दिया है। ऑक्सीजन से लेकर एंबुलेंस और खाने तक, ये लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपको भी अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। हर रुपया महत्व रखता है। जय हिंद। पोस्ट में फरहान ने एक्सल मूवीज के पार्टनर रितेश सिधवानी को भी मेंशन किया है।

सोशल मीडिया पर दे रहे हैं कोरोना से जुड़ी सही जानकारी

फरहान अख्तर डोनेशन के अलावा भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों की मदद कर रहे हैं। एक्टर लगातार अपने ट्विटर पर ऑक्सीजन, एंबुलेंस और दवाइयों की सही जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही एक्टर ने फैंस और जनता से ज्यादा से ज्यादा डोनेट करने की अपील भी की है। फरहान अख्तर जल्द ही राकेश ओमप्रकाश के निर्देशन में बनी फिल्म तूफान में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में फरहान एक मुक्केबाज की भूमिका में हैं। फिल्म को पहले सिनेमाघरों के लिए तैयार किया गया था हालांकि महामारी को देखते हुए अब इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा।

सेलेब्स और रूमर्स : प्रेग्नेंसी और सुसाइड करने की उड़ती अफवाहों पर दिया इलियाना डिक्रूज ने अपना रिएक्शन, बोलीं– बहुत दुख होता है

बॉलीवुड सेलेब्स अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ से जुड़ी खबरों से ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। खबरों के साथ–साथ सेलेब्स से जुड़ी अफवाहें भी कई बार चर्चा का विषय बन जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इलियाना डिक्रूज के साथ जिनकी प्रेग्नेंसी और सुसाइड की खबरें कुछ महीनों पहले जारी हुई थीं। अब एक्ट्रेस ने इस तरह की फेक न्यूज और अफवाहों पर अपना रिएक्शन देते हुए इन्हें बेतुका बताया है। बता दें कि साउथ इंडस्ट्री में पहचान बनाने के बाद इलियाना ने बॉलीवुड में बर्फी, मैं तेरा हीरो और रुस्तम जैसी फिल्में दी हैं।

2018 में उड़ी थी प्रेग्नेंसी की अफवाह

हाल ही में बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में इलियाना ने फेक न्यूज और अफवाहों पर कहा, मुझसे जुड़ी कुछ अफवाहें हैं। एक ऐसी खबर थी जिसमें मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने अबॉर्शन करवाया था। ये काफी दुखी करने वाला था। सच कहूं तो कुछ लोग ऐसी ही चीजें लिखते हैं। ये बहुत बेतुका है। बता दें कि साल 2018 में खबरें उड़ी थीं कि इलियाना डिक्रूज प्रेग्नेंट हैं। हालांकि एक्ट्रेस ने इन सभी अफवाहों को साफ करते हुए उसी समय सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसके साथ उन्होंने लिखा था, नॉट प्रेग्नेंट।

कोविड अपडेट:रणधीर कपूर बोले-

ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी जल्दी घर आऊंगा, स्वरा भास्कर की मां हुईं रिकवर लेकिन जैस्मीन भसीन को हुई परेशानी

हाल ही में रणधीर कपूर को कोरोना संक्रमण के कारण हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। अब उन्होंने अपनी सेहत के बारे में अपडेट देते हुए कहा है कि वे पहले से बेहतर मेहसूस कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें घर वापस जाने की परमीशन मिल जाएगी। रणधीर दो दिन तक आईसीयू में थे। हालांकि उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी और न ही उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत हुई, उन्हें केवल बुखार था।

स्वरा की मां इरा ने कोरोना को हराया

दूसरी ओर स्वरा भास्कर की मां इरा कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गई हैं। स्वरा ने सोशल मीडिया पर मां की एक फोटो के साथ यह जानकारी शेयर की। स्वरा ने लिखा– यह बहुत बुरा समय है, लेकिन इस बीच कुछ अच्छी खबर भी शेयर करती हूं। मां और बिकेश, इन दोनों को कोरोना संक्रमण हुआ था अब वे दोनों ही निगेटिव हो गए हैं। 14 दिन बाद, जब वे बुखार और ऑक्सीजन के उतार–चढ़ाव से जूझ रहे थे। बहुत ही अच्छा और लकी महसूस कर रही हूं। आप सभी की शुभकामनाओं का शुक्रिया। जो लोग पीड़ित हैं उनके परिवारों के लिए दुआ करती हूं।

जैस्मीन को जूझना पड़ा बेड के लिए

बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट रहीं जैस्मीन भसीन की मां को कोरोना संक्रमण के बाद हॉस्पिटल में एक बेड के लिए परेशान होना पड़ा। जैस्मीन ने सोशल मीडिया पर लिखा– दुखद और दिल तोड़ने वाला। हर दिन मौतें, लोग सड़कों पर बेड्स और ऑक्सीजन खोज रहे हैं। दो दिन पहले मेरी मां भी इसी हाल में थी। एक बेड को खोजना मुश्किल हो गया था। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेरे बुजुर्ग पिता चक्कर लगा रहे थे। दूसरे भी इन हालातों से गुजर रहे हैं।

कोरोना का असर-

18 दिन से अटकी पड़ी है रणवीर सिंह स्टारर 'सर्कस' की सिर्फ एक दिन की शूटिंग,

ऊटी में नहीं मिली शूट की इजाजत तो महबूब स्टूडियो में बनाया सेट

कोविड की दूसरी लहर ने मेगाबजट फिल्मों की शूटिंग पर भी ब्रेक लगा दिया है। मजबूरन मेकर्स को शूटिंग करने के नए तरीके निकालने पड़ रहे हैं। लेकिन, कुछ फिल्मों के लिए कोई तरीका काम नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर रणवीर सिंह और जैकलीन फर्नांडीज स्टारर फिल्म फ्सर्कस को ही ले लीजिए। वैसे तो यह फिल्म तकरीबन पूरी शूट हो चुकी है, पर इसकी सिर्फ एक दिन की शूटिंग बीते 18 दिनों से अटकी पड़ी है।

ज्यादा क्रू मेंबर्स होने के चलते नहीं मिली शूटिंग की इजाजत

फिल्म से जुड़ सूत्रों ने बताया, फ्पूरी टीम 12 अप्रैल को शूटिंग के लिए ऊटी जाने वाली थी। वहां डबल रोल में रणवीर सिंह के जैकलीन और पूजा हेगड़ के साथ रोमांटिक सीन फिल्माए जाने थे। इन सभी सीन के बैकग्राउंड में 50 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्टों को रखा जाना था। पूरी यूनिट को संभालने के लिए 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स की टीम भी जाती, मगर ऊटी प्रशासन ने वहां इतनी तादाद में शूटिंग करने की इजाजत नहीं दी। ऐसे में मेकर्स ने महबूब स्टूडियो के इंडोर में ही ऊटी का सेट बनाना शुरू कर दिया, मगर कोविड प्रोटोकॉल के चलते अब महाराष्ट्र में भी शूटिंग बंद होने के चलते वह काम भी अटक गया है।

वीएफएक्स के जरिए दिखाए जाएंगे सर्कस के जानवर

फिल्म से जुड़े ऑफिशियल्स ने बताया, फ्फिल्म का टाइटल जरूर 'सर्कस' है, मगर इसमें बंद पिंजरों में ही असली जानवरों के साथ शूटिंग नहीं की जा रही। फिल्म में 80 फीसदी से ज्यादा वीएफएक्स वर्क होगा। मेकर्स ने स्टूडियो में जानवरों के स्टेच्यू लगाकर सीन शूट कर लिए हैं। अब वीएफएक्स की मदद से उन्हें जीवंत किया जाएगा। जैसा 'टोटल धमाल' में किया गया था। फिल्म के लिए रणवीर ने उड़ती गाड़ियों के साथ भी कुछ स्टंट सीन शूट किए हैं। मगर उन्हें भी जुगाड़ लगाकर स्टूडियो के अंदर ही शूट किया गया है। 'सर्कस' रोहित शेट्टी की पहली ऐसी फिल्म होगी, जिसकी ज्यादा से ज्यादा शूटिंग स्टूडियोज के अंदर ही की गई है।

बड़े बजट की ये फिल्में भी अटकीं

- 'सर्कस' के अलावा और भी कई बड़े बजट की फिल्में हैं, जिनकी शूटिंग अटकी हुई है। जानिए...
- आलिया भट्ट स्टारर ' गंगूबाई' का भी महज एक दिन का काम बाकी है।
- अजय देवगन की 'मेडे' और फ्मैदान।
- शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर 'पठान'।
- सलमान–कटरीना की 'टाइगर 3'।
- वरुण धवन की 'जुग जुग जियो'।

कोरोना से रिकवर होते ही काम पर लौटे आमिर खान, लद्दाख में शूट हो रहा है लाल सिंह चड्ढा फिल्म का फाइनल शेड्यूल

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान कुछ दिनों पहले ही कोविड 19 की चपेट में आ गए थे जिससे अब एक्टर रिकवर हो चुके हैं। रिकवर होने के तुंरत बाद ही एक्टर ने बिना ब्रेक लिए दोबारा काम पर वापसी कर ली है। एक्टर अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की बची हुई शूटिंग लद्दाख में कर रहे हैं जहां से लगातार तस्वीरें और वीडियोज सामने आ रही हैं। हाल ही में आई ई–टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में लाल सिंह चड्ढा फिल्म का अहम हिस्सा शूट किया जा रहा है। यहां एक्टर 45 दिनों तक शूट करने वाले हैं। इस फिल्म में पहले विजय सेतुपति भी आमिर खान के साथ नजर आने वाले थे हालांकि अब उन्हें नाग चैतन्य ने रिप्लेस कर दिया है। अब जल्द ही नाग चैतन्य भी शूटिंग खत्म करने के लिए लद्दाख पहुंचने वाले हैं।

कोरोना महामारी के चलते बदली गई लोकेशन

आमिर खान की फिल्म में कारगिल वॉर का सीन दिखाया जाना है जिसकी शूटिंग पहले विदेश में की जानी थी। आमिर खान लोकेशन देखने भी गए थे हालांकि लॉकडाउन और महामारी के चलते विदेश में शूटिंग किया जाना मुमकिन नहीं हो सका। अब फिल्म में युद्ध का सीन दिखाने के लिए लद्दाख में ही कारगिल का सेट तैयार किया गया है।

फॉरेस्ट गंप की हिंदी रीमेक है लाल सिंह चड्ढा

आमिर खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की हिंदी रीमेक होने वाली है। ऑरिजिनल फिल्म में टॉम हैंक्स ने लीड रोल निभाया था। इस फिल्म को 2020 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया जाने वाला था हालांकि लॉकडाउन के चलते शूटिंग पूरी नहीं हो सकी। फिलहाल मेकर्स इसे इस साल के आखिर तक रिलीज करने की तैयारी में है।

बड़े दिल वाला

विजय देवरकोंडा ने अस्पताल में भर्ती फैन की आखिरी ख्वाहिश की पूरी, नम आंखों के साथ कहा- तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं

जल्द ही फिल्म लीगर से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री करने वाले विजय देवरकोंडा ने हाल ही में अपने एक फैन की आखिरी ख्वाहिश पूरी की है। उनका फैन हेमंत कोरोना पॉजिटिव था और अस्पताल में भर्ती था जब उसने विजय से बात करने की इच्छा जताई थी। जब विजय को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी टीम भेजकर हेमंत से वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत की। अपने फैन से बात करते हुए एक्टर अपने आंसू नहीं रोक सके। इस बेहद खास फैन मूमेंट को एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। विजय ने अपने फैन के साथ वीडियो कॉलिंग करते हुए एक स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। इसके साथ एक्टर ने लिखा, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं हेमंत.. मुझे बहुत खुशी है कि अपनी बात हुई और मुझे तुम्हारी मीठी सी मुस्कान देखने का मौका मिला। तुम्हारा प्यार महसूस हुआ और तुम्हें थोड़ा प्यार दिया। आखों में आंसुओं के साथ मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं। सबका शुक्रिया जिसने मुझे इस छोटे स्वीट से लड़के से कनेक्ट करने में मेरी मदद की।

ये थे विजय के लिए हेमंत के आखिरी शब्द

- इस वीडियो कॉलिंग के बाद हेमंत ने विजय से उनकी राउडी ब्रांड की एक टी–शर्ट की गुजारिश की थी। साथ ही हेमंत ने कहा, अन्ना, आपसे बात करने के बाद बहुत आराम मिला है। बहुत अच्छा होता अगर मुझे कोविड ना होता।
- विजय देवरकोंडा जल्द ही पुरी जगन्नाथ के निर्देशन में बन रही फिल्म लीगर से बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे भी लीड रोल में नजर आने वाली हैं जिसे 9 सितंबर 2021 में रिलीज करने के लिए शेड्यूल किया गया है। फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

फूड टेक्नोलॉजी में भरपूर अवसर

भारत में करीब 30 करोड़ की आबादी प्रोसेस्ड और डिब्बाबंद खाद्य-पदार्थों का इस्तेमाल करती है। इतना ही नहीं, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक देश है। प्रोसेस्ड फूड तैयार करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां दुनियाभर से जब भारत का रुख कर रही हैं। ऐसे में फूड टेक्नोलॉजी का भविष्य कितना सुनहरा है इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है।

क्वालिफिकेशन

फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी अथवा मैथमेटिक्स विषयों के साथ 102 में कम से कम 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। एमएससी कोर्स करने के लिए फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित विषयों में स्नातक की डिग्री आवश्यक है।

किस तरह के कोर्स

-बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी (3 वर्ष)

-बीएससी इन फूड न्यूट्रीशियन ऐंड प्रिजरवेंशन (3 वर्ष)

-बीटेक इन फूड इंजीनियरिंग (4 वर्ष)

-एमएससी इन फूड टेक्नोलॉजी (2वर्ष)।

किस तरह की होती है पढाई

फूड टेक्नोलॉजी तथा इससे संबंधित कोर्सेज के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के उचित रख-रखाव से लेकर पैकेजिंग, फ्रीजिंग आदि की तकनीकी जानकारियां शामिल होती हैं। इसके अंतर्गत पोषक तत्वों का अध्ययन, फल, मांस, वनस्पति व मछली प्रसंस्करण आदि से संबंधित जानकारियां भी दी जाती हैं।

पर्सनल स्किल

फूड टेक्नोलॉजिस्ट को साइंटिफिक सोच वाला होना जरूरी है। उसे टेक्नोलॉजी डेवलॅपमेंट, हेल्थ व न्यूट्रीशन में रुचि होनी चाहिए। इसके साथ ही जिम्मेदारी व टीम के साथ काम करना भी आवश्यक है। उसमें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए।

वर्क प्रोफाइल

विकसित देशों की तुलना में भारत में फूड टेक्नोलॉजी एवं प्रोसेसिंग उद्योग तुलनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ है। यूं तो हमारे देश में फूड टेक्नोलॉजी एवं प्रोसेसिंग उद्योग सदियों पुराना है। प्राचीनकाल से ही महिलाएं घरों में अचार-मुरब्बा, अमचूर आदि का निर्माण करती रही हैं, परंतु यह अभी भी कुटीर उद्योग ही है। परंतु अब धीरे-धीरे विश्व के साथ कदमताल करते हुए आधुनिक तकनीक वाली फूड टेक्नोलॉजी एवं प्रोसेसिंग इकाइयां हमारे देश में लगाई जा रही हैं। इन इकाइयों से उत्पादित उत्पादों की गुणवत्ता विश्व कोटि की होती है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के तहत वे सभी कार्य शामिल हैं, जिनसे खाने वाली चीजों की गुणवत्ता, स्वाद और रंग-रूप बरकरार रह सके। जैसे- मक्खन, सॉफ्ट ड्रिंक, जेम व जेली, फ्रूट जूस, बिस्कुट, आइसक्रीम आदि। इसके अलावा वह कच्चे और बने हुए माल की गुणवत्ता, स्टोरेज तथा हाइजिन आदि की निगरानी भी करता है।

कहां मिलेगी नौकरी

कृषि पर आधारित फूड टेक्नोलॉजी (खाद्य प्रौद्योगिकी) के क्षेत्र में करियर की काफी अच्छी संभावनाएं हैं। एक अनुमान के मुताबिक, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग ढ़ाई लाख से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। फूड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बहुत बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री की प्रोसेसिंग कर उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है तथा बेहतर गुणवत्ता और पोषक तत्वों से युक्त भोज्य सामग्री बाजार में उपभोग हेतु उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे रोजगार के अवसरों में भी भारी वृद्धि होगी। फूड टेक्नोलॉजिस्टों के लिए विभिन्न संगठनों में रोजगार अच्छा मौका है। इनमें सरकारी, सहकारी तथा विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं। फूड टेक्नोलॉजिस्ट प्रोडक्ट डेवलॅपमेंट, मैनेजर, रिसर्चर, क्वालिटी एश्योर मैनेजर, लेबोरेट्री सुपरवाइजर, फूड पैकिंग मैनेजर, फूड प्रोसेसिंग टेक्नीशियन, बीआईएस-एग्मार्क इंस्पेक्ट, खाद्य इंस्पेक्टर आदि के रूप में भी नियुक्ति होती है। फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स पूरा कर लेने के बाद फूड इंडस्ट्री, होटलों, अस्पतालों, पैकेजिंग इंडस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक फैक्टरी, राइस मिल आदि में नौकरी प्राप्त की जा सकती है। आप फूड टेक्नोलॉजी कोर्स करके स्वरोजगार भी कर सकते हैं। इसके अलावा तकनीकी संस्थाओं में शिक्षक या प्रशिक्षक के पद पर भी कार्य कर सकते हैं।

भविष्य में हैं ढेरों संभावनाएं

कैबिनेट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की लगभग 30 करोड आबादी संशोधित व डिब्बाबंद खाद्य-पदार्थ इस्तेमाल करती है। वैसे भी भारत फल और सब्जियां पैदा करने वाला विश्व का दूसरा सबसे बडा देश है। एक अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में डिब्बा बंद खाद्य-पदार्थों का कारोबार 30 से 35 अरब रुपये वार्षिक है। यही कारण है कि यह क्षेत्र मल्टीनेशनल कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी आकर्षण के कारण कई मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे मैक्डोनॉल्ड, पेप्सी, कोका कोला व हिन्दुस्तान लीवर अपना कारोबार भारत में बढाती जा रही है।

सैलॅरी पैकेज

इस क्षेत्र में शुरुआती स्तर पर आप 8 से 12 हजार रुपये प्रतिमाह आसानी से कमा सकते हैं। अनुभव के बाद 30 हजार रुपये प्रतिमाह या इससे भी ज्यादा कमाया जा सकता है। यदि आप स्वरोजगार से जुडते हैं, तो आपकी कमाई और बढ सकती है।

इंस्टीट्यूट वॉच....

-यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली

-इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मैदानगढी, दिल्ली

-जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रिकल्चर ऐंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, उत्तराखंड

-बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी, उत्तर प्रदेश

-कानपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर, उत्तर प्रदेश

-कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता

-महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना, मध्यप्रदेश

-गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर, पंजाब

-मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई

-नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर

-सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर

-बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, रांची, बिहार

इन फील्ड्स में हैं बेशुमार मौके, मिलेगी लाखों में सैलरी

12वीं के बाद चाहते हैं शानदार करियर?

12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित होने शुरू हो गए हैं। जल्द ही सभी राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं के 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे में जो युवा 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं या करेंगे। उनके सामने करियर को लेकर काफी उलझन की स्थिति होगी कि वह किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएं, जहां उन्हें वेतन भी अच्छा मिले और ग्रोथ के भी भरपूर मौके रहें। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें आप 12वीं के बाद कोर्स कर सकते हैं और शानदार करियर बना सकते हैं-

लॉजिस्टिक का क्षेत्र : आज के दौर में लॉजिस्टिक के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और तकनीक के इस दौर में इस क्षेत्र में काफी ग्रोथ के चांस हैं। खासकर कोरोना के बाद जहां लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। ऐसे में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक के क्षेत्र पर लोगों की निर्भरता बढ़ी है। ई-कॉमर्स कंपनियों के विस्तार के साथ ही लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं पैदा होंगी। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपने करियर के बारे में नहीं सोचा है तो लॉजिस्टिक का फील्ड में करियर बनाना समझदारी भरा फैसला हो सकता है। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए युवा 12वीं के बाद लॉजिस्टिक्स में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। साथ ही बीबीए या एमबीए करने का भी विकल्प है। आप अपने रुझान के अनुसार, बिजनेस लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट आदि क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं।

फॉरेन लैंग्वेज का क्षेत्र : ग्लोबलाइजेशन के दौर में विदेशी भाषाओं को क्षेत्र में अपार संभावनाएं बनी हैं। कंपनियां दुनियाभर में बिजनेस करती हैं, ऐसे में उन्हें कम्यूनिकेशन के लिए ऐसे पेशवरों की जरूरत है, जो विदेशी ग्राहकों या कंपनियों से कम्यूनिकेट कर सकें. बीपीओ और कॉल सेंटर्स में भी विदेशी भाषा जानने वाले लोगों की अच्छी खासी डिमांड है. खास बात ये है कि इस क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं को अच्छी सैलरी भी मिलती है। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। इसके बाद विदेशी भाषाओं के डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला लिया जा सकता है। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए स्कूल ऑफ लैंग्वेज, जेएनयू यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली, बीएचयू, वाराणसी आदि संस्थानों में एडमिशन लिया जा सकता है।

वीडियो एडिटिंग का क्षेत्र : इंसान को अपने जीवन में मनोरंजन जरूर चाहिए. यही वजह है कि मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। क्रिएटिव लोगों के लिए इस क्षेत्र में काफी मौके हैं. मीडिया के क्षेत्र में वीडियो एडिटिंग भी एक शानदार विकल्प है। सोशल मीडिया के आगमन के बाद वीडियो एडिटर्स की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ी है और भविष्य में भी रहेगी। वीडियो एडिटर बनने के इच्छुक युवा 12वीं के बाद वीडियो एडिटिंग का सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। डिग्री कोर्स करने के लिए स्नातक होना जरूरी है। क्रिएटिव लोग इस क्षेत्र में खासे सफल हो सकते हैं।

उड़ने का सपना साकार करना है तो बनाएं एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कॅरियर

एविएशन इंडस्ट्री इन दिनों उफान पर है। जिसके चलते इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। वैसे, इन दिनों भारतीय एविएशन कंपनियों के साथ-साथ विदेशी एविएशन कंपनियां भी तेजी से पांव पसारने लगी हैं। ऐसे में विमानों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए एयरोनॉटिकल इंजीनियरों की मांग भी बढ़ रही है। एयर इंडिया, इंडिगो, इंडियन एयरलाइंस, स्पाइस जेट, ब्लू डार्ट और एशिया एविएशन जैसे एयरलाइंस के अलावा, सरकारी उड्डयन विभागों में इनके लिए ढेरों अवसर हैं। पीसीएम से 12वीं पास करने वाले छात्र के लिए एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में रोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं।

क्या है एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग?

एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है, जिसमें एयरोनॉटिक्स और स्पेस साइंस दोनों का अध्ययन किया जाता है। चुनौतियों से भरपूर इस क्षेत्र में काम करते हुए आपको एविएशन, अंतरिक्ष और रक्षा से संबंधित अनुसंधान और नई टेक्नोलॉजी के विकास का अवसर मिलता है। एयरोनॉटिकल इंजीनियर के रूप में आप निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं, जैसे- स्ट्रक्चरल डिजाइन, नेविगेशनल गाइडेंस ऐंड कंट्रोल सिस्टम, इंस्ट्रूरमेंटेशन ऐंड कम्युनिकेशन या प्रोडक्शन मेथॅड, मिलिट्री एयर क्राफ्ट, पैसेंजर प्लेन, हेलीकॉप्टर, सेटेलाइट, रॉकेट इत्यादि।

योग्यता और कोर्स

एयरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए आपके पास बीई/बीटेक (एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग) अथवा कम से कम एयरोनॉटिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए। विभिन्न कॉलेजों और आईआईटी द्वारा एयरोनॉटिक्स में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करवाई जाती है, जबकि कई पॉलिटेक्निक्स द्वारा एविएशन में डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथमेटिक्स विषयों के साथ बारहवीं या उसके समकक्ष परीक्षा पास करने वाला कोई भी व्यक्ति बीई/बीटेक में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। यदि आईआईटी में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो आपको आईआईटी-जेईई परीक्षा पास करनी होगी। देश में कुछ संस्थान एविएशन में पोस्ट ग्रेजुएट (एमटेक) और डॉक्टोरल प्रोग्राम (PHD) भी कराते हैं।

व्यक्तिगत योग्यता

एयरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए आपके पास तीक्ष्ण प्रेक्षण दृष्टि और समस्याओं को आसानी से सुलझाने की कला होनी चाहिए। इस काम के लिए मेनुअल, टेक्नीकल व मैकेनिकल रुझान होना जरूरी है। आपके पास बेहतर तार्किक क्षमता, संप्रेषण योग्यता और कंप्यूटर पर तेजी से काम करने की क्षमता होनी चाहिए। इन्हें दबाव में भी काम करना आना चाहिए। एक एयरोनॉटिकल इंजीनियर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह वह शारीरिक रूप से फिट हो तथा खासकर विमान पर यात्रियों या माल के चढ़ने-उतरने के दौरान तेजी से विमान की जांच व मरम्मत का काम संभाल सके। उनकी आंखों की दृष्टि भी ठीक होनी चाहिए और वर्णाधता किस्म का कोई दोष नहीं होना चाहिए।

प्रवेश का आधार

ग्रेजुएट कोर्सो (बीई/बीटेक) में प्रवेश मेरिट के आधार पर होता है। आईआईटी में प्रवेश के लिए बारहवीं कक्षा (PCM) में प्राप्त अंक एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाती है। अन्य संस्थान अपनी अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर (जैसे-एआईईईई) पर अन्य प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। अधिकतर संस्थान जेईई में प्राप्त स्कोर के आधार पर ही छात्रों को प्रवेश देते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस लर्निंग से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के इच्छुक डिप्लोमा होल्डर्स या वर्किंग व्यक्तियों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा असोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स नामक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह परीक्षा एयरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया (एएसआई) द्वारा आयोजित की जाती है।

कोर्स की अवधि

एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का बीई/बीटेक कोर्स चार साल का होता है, जबकि डिप्लोमा कोर्स की अवधि दो-तीन साल होती है।

विदेश में शिक्षा

अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों में भी एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अंडरग्रेजुएट लेवॅल कोर्स कराया जाता है। इन संस्थानों में अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, एम्ब्री-रिडल एयरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यहां एयरोस्पेस इंजीनियरिंग का कोर्स भी कराया जाता है। अंडरग्रेजुएट लेवॅल पर एडमिशन लेने के इच्छुक छात्रों को एसएटी (सैट) और टीओईएफएल (टॉफेल) पास करना आवश्यक है, जबकि ग्रेजुएट लेवॅल पर एडमिशन लेने के लिए आपको जीआरई या टॉफेल उत्तीर्ण करना होगा।

रोजगार के अवसर

आज दक्ष एयरोनॉटिकल इंजीनियरों की सरकारी व निजी एयरलाइन कंपनियों, विमान निर्माता कंपनियों और इसके रखरखाव की सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों में समान रूप से जबरदस्त मांग है। ये रक्षा अनुसंधान व विकास संबंधी संस्थानों, नेशनल एयरोनॉटिकल प्रयोगशालाओं, एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट संस्थापनाओं, नागरिक उड्डयन विभाग, प्रतिरक्षा सेवाओं और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में भी रोजगार पा सकते हैं। इस विधा के इंजीनियर्स विमान के डिजाइन, विकास और रखरखाव संबंधी क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, वहीं इससे जुड़े प्रोफेशनल्स विभिन्न संस्थानों में प्रबंधकीय व शिक्षण के पदों पर भी काम कर सकते हैं।

सैलरी पैकेज

इस क्षेत्र में सैलरी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव पर निर्भर करता है। सरकारी या पब्लिक सेक्टर मसलन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेट्रीज (एनएएल) में आपका शुरुआती वेतन 8,000 से 10,000 रुपये मासिक तक हो सकता है (भत्तों को छोड़कर)। प्राइवेट सेक्टर में आपके वेतन का निर्धारण मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है, जो अमूमन 8,000 से 15,000 रुपये प्रतिमाह तक हो सकता है। इसके अलावा, आपको कुछ भत्ते व अन्य सुविधाएं भी मिल सकती हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जिनके पास मैनेजमेंट की डिग्री भी है, उन्हें शुरुआती स्तर से 10,000 से 40,000 रुपए मासिक वेतन व अन्य लाभ तथा सुविधाएं मिल सकती हैं। विदेशों में भी आपके लिए कई मौके हैं। अमेरिका के नासा जैसे संस्थान में यदि आपको नौकरी मिलती है, तो वहां आपका शुरुआती वेतन 1,00,000 से 1,50,000 डॉलर तक हो सकता है।

इंस्टीट्यूट वॉच...

-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस, बेंगलुरु

-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, देहरादून।

-आईआईटी (खडगपुर, मुंबई, कानपुर, चेन्नई)।

-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिकल साइंस, नई दिल्ली।

-भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स, पटना एयरपोर्ट, पटना।

-एकेडमी ऑफ एरोस्पेस ऐंड एविएशन, इंदौर।

-पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़।

यदि आप जानवरों से करते हैं प्यार तो बनें एनिमल ट्रेनर

जो लोग एनिमल लवर होते हैं, वह अगर चाहें तो वह ऐसा कार्यक्षेत्र चुन सकते हैं, जिनमें उनका लगभग सारा समय जानवरों के साथ ही बीते। ऐसा ही एक क्षेत्र है एनिमल ट्रेनिंग। एनिमल ट्रेनिंग वास्तव में काफी रोमांचक क्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति सिर्फ जानवरों को ही काफी कुछ नहीं सिखाता, बल्कि उनसे भी उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एनिमल ट्रेनिंग में किस तरह बनाएं कॅरियर

क्या होता है काम : एक एनिमल ट्रेनर का काम काफी चैलेंजिंग व कठिन होता है, जो विभिन्न तरह की तकनीकों को अपनाकर जानवरों को ट्रेन करते हैं। वे जानवरों को किसी विशेष कमांड व स्थितयों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। साथ ही वह जानवरों को सिक्योरिटी, एंटरटेनमेंट, रेसिंग व दूसरों की मदद के लिए प्रशिक्षित करते हैं। आमतौर पर, एनिमल ट्रेनर कई तरह के ट्रेनर होते हैं, जैसे- पालतू जानवर ट्रेनर, सर्विस एनिमल ट्रेनर, मैरिन मैमेल ट्रेनर, एक्सोटिक एनिमल ट्रेनर, घोड़ा प्रशिक्षक आदि।

योग्यता : एनिमल ट्रेनर बनने के लिए कोई औपचारिक शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहीं है, लेकिन व्यक्ति को कम से कम 12वीं पास या कम से कम हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा समुद्री स्तनधारी ट्रेनर बनने के लिए व्यक्ति को जूलॉजी, जीव विज्ञान, समुद्री जीव विज्ञान, पशु विज्ञान या मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक के बाद, आप एनिमल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करके इस क्षेत्र में कदम बढ़ा सकते हैं।

व्यक्तिगल विशेषता : इस क्षेत्र में कॅरियर देख रहे छात्रों को जानवरों से प्यार करना, अपने काम के प्रति जुनून व धैर्य होना बेहद जरूरी है। उन्हें जानवरों को अच्छी तरह हैंडल करना, उन्हें अच्छी तरह पालना व उनका सम्मान करना चाहिए। चूंकि जानवर मुंह से बोलकर अपनी बात नहीं बता सकते, इसलिए एनिमल ट्रेनर के पास अच्छे शिक्षण कौशल होने चाहिए। साथ ही उन्हें जानवरों की गतिविधि व मनोदशा में समझने में सक्षम होना चाहिए। इसी तरह, समुद्री जानवरों के प्रशिक्षण से जुड़े लोगों को तैराकी और डाइविंग तकनीक से परिचित होना चाहिए। इन सब के अलावा उनमें शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति अच्छी होनी चाहिए।

कॅरियर विकल्प : एनिमल ट्रेनर पुलिस फोर्स, एनिमल शेल्टर, चिड़ियाघर, अस्तबल, एक्वेरियम, प्राणी उद्यान, घुड़सवारी क्लब, हॉर्स फार्म, हॉर्स राइडिंग क्लब आदि में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा, आप पशु चिकित्सा अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, पालतू जानवर के स्टोर व रिसर्च फैसिलिटी में भी काम कर सकते हैं। वहीं कुछ एनिमल ट्रेनर फीचर फिल्मों या विज्ञापनों के लिए जानवरों के साथ काम करते हैं।

आमदनी : एक एनिमल ट्रेनर का पारिश्रमिक स्थान व पशु के आकार के अनुसार भिन्न होता है। एक डॉग ट्रेनर की तुलना में एक घोड़ा ट्रेनर को बहुत अलग पैमाने पर भुगतान किया जाता है। आप अपने कॅरियर की शुरूआत 10000 रूपए मासिक वेतन से कर सकते हैं। इसके बाद आपके कौशल व अनुभव के आधार पर आपकी आमदनी बढ़ती जाती है। एक अनुभवी व्यक्ति अपने काम के लिए घंटों के अनुसार भी चार्ज कर सकता है।

नंदीग्राम सीट से हार के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका

ममता बनर्जी की उम्मीदों को बड़ा झटका

कोलकाता,पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से हार के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। अपने पूर्व सहयोगी से नजदीकी मुकाबले में हार के बाद वोटों की दोबारा गिनती की उनकी मांग को खारिज कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला अंतिम है और इसे केवल हाई कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। इस बीच नंदीग्राम में आरओ रहे अधिकारी को सुरक्षा प्रदान की गई है। चुनाव आयोग ने मीडिया में उन रिपोट्र्स को खारिज किया है जिनमें कहा गया है कि नंदीग्राम में दोबारा काउंटिंग होगी। आयोग ने कहा है कि किसी विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) आरपी एक्ट, १९५१ के तहत अर्ध-न्यायिक क्षमता में स्वतंत्र रूप से और चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के आधार पर अपने काम को अंजाम देते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि नियम के आधार पर यदि दोबारा गिनती की मांग की जाती है तो रिटर्निंग ऑफिसर उसे स्वीकार कर सकते हैं या असंगत लगने पर खारिज कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि आरओ के फैसले को आरपी एक्ट १९५१ की धारा ८० के तहत चुनाव याचिका

के जरिए ही चुनौती दी जा सकती है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को जारी बयान में कहा, ''नंदीग्राम में गिनती खत्म होने के बाद एक प्रत्याशी के इलेक्शन एजेंट ने दोबारा मतगणना की मांग की थी जिसे आरओ ने अपने सामने मौजूद तथ्यों को देखते हुए मौखिक आदेश में खारिज कर दिया। इसके बाद परिणाम की घोषणा की गई थी। ऐसे मामले में अब हाई कोर्ट में ईपी दायर करने का ही विकल्प बचता है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए मतगणना में गड़बड़ी के आरोपों को भी खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि सभी काउंटिंग टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर था और उन्होंने अपनी रिपोट्र्स में किसी तरह की गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं दिया है। सभी राउंड के बाद आरओ ने सभी प्रत्याशियों को मिले वोट की संख्या की एंट्री की थी और इसे डिस्प्ले बोर्ड पर दर्शाया गया था,

जिसे काउंटिंग एजेंट आसानी से देख सकते थे। पूरी काउंटिंग प्रक्रिया के दौरान किसी ने कोई शंका नहीं जाहिर की थी और पूरी प्रक्रिया बिना किसी रूकावट के चली।

हर राउंड के बाद सभी एजेंट को रिजल्ट की कॉपी दी जा रही थी।

बंगाल में हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने ५ मई को देशव्यापी धरने का किया ऐलान

क्रांति समय दैनिक

कोलकाता,पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद राज्य में हो रहीं कई हिंसक घटनाओं को लेकर बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी पांच मई को देशव्यापी धरना करने जा रही है। मालूम हो कि बीजेपी का आरोप है कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं, जिसमें कई लोगों की हत्याएं भी की गई हैं। इसके अलावा भी राज्य में व्यापक पैमाने पर हिंसा देखने को मिली जिसमें कथित तौर पर झड़प और दुकानों को लूटे जाने के दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई तो कई घायल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले की घटना में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी ने एक पार्टी कार्यालय में आगजनी का वीडियो साझा किया है जिसमें बांस की बल्लियां और छत जलती हुई नजर आ रही हैं और परेशान लोगों को चिल्लाते हुए भागते देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर मृत व्यक्तियों की तस्वीरें और

क्रांति समय फाउंडेशन (NGO)

एक दुकान से कपड़े लूट कर भागते लोगों की फुटेज वायरल हो रही है। बीजेपी का दावा है कि उसके कम से कम छह कार्यकर्ता और समर्थक हमलों में मारे गए हैं जिनमें एक महिला भी शामिल है। भाजपा इसका आरोप तृणमूल पर लगा रही है। बीजेपी ने पत्रकारों के साथ एक वीडियो साझा किया जिसमें नंदीग्राम में पार्टी दफ्तर में हुई तोड़फोड़ को दिखाया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सीट पर भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थीं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रदेश के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और कोलकाता के पुलिस आयुक्त को तलब कर उन्हें शांति बहाल करने के निर्देश दिए।

बंगाल में हिंसा पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताई चिंता

क्रांति समय दैनिक

कोलकाता (ईएमएस)। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जारी हिंसा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की थी और राज्य में फैली हिंसा को लेकर चिंता जताई थी। गवर्नर धनखड़ ने कहा, 'पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉल किया था और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्ति की। मैंने भी इस पर चिंता जताई और बताया कि राज्य में तोड़फोड़, लूट और हत्याओं का दौर लगातार जारी है। राज्य में कानून व्यवस्था को संभालने के लिए तत्काल एक्शन लिए जाने की जरूरत है।' इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव भूपेंद्र यादव सोमवार को बंगाल पहुंच गए हैं। बीजेपी की ओर से बंगाल में कार्यकर्ताओं के खिलाफ जारी हिंसा के विरोध में ५ मई को देशव्यापी धरने का भी ऐलान किया गया है। बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया है, 'बंगाल में नतीजों के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ओर से जारी भीषण हिंसा के विरोध में बीजेपी ने देशव्यापी धरने का ऐलान किया है। यह बीजेपी की ओर से मंडल स्तर पर किया जाएगा। धरने के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ पालन किया जाएगा। दोनों नेता राज्य में राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले बीजेपी की ओर से हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा गया था कि यह लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद स्वप्न दासगुप्ता ने इस बीच ट्वीट कर राज्य के मुख्य न्यायाधीश से हिंसक घटनाओं का स्वत- संज्ञान लेने की अपील की है और कहा है कि उन्हें प्रशासन को आदेश देना चाहिए कि हिंसा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। इससे पहले सोमवार को गवर्नर ने राज्य के डीजीपी को तलब कर हिंसा पर चिंता जताई थी। वहीं बंगाल में कई सीटों पर चुनाव लड़ने वाली एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिंसा को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा, 'जीने का अधिकार मूलभूत अधिकार है। यह किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य है कि वह लोगों की जान बताए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर वह अपनी ड्यूटी में फेल है। हम किसी भी सरकार की असफलता की आलोचना करते हैं। भले ही वह देश के किसी भी हिस्से या राज्य की सरकार हो। बता दें कि राज्य में चुनाव के बाद भड़की हिंसा के लिए बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी दो दिवसीय

सार–समाचार

भारत के बंटवारे में हुई थी ऐसी हिंसा हम जंग को तैयार- जेपी नड्डा

कोलकाता,चुनाव नतीजों के बाद से जारी हिंसा के बीच बीजेपी चीफ जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। कोलकाता में एयरपोर्ट पर उतरते ही जेपी नड्डा ने टीएमसी को हिंसा पर चेतावनी देते हुए कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई के लिए तैयार हैं। जेपी नड्डा ने कहा, 'वैचारिक लड़ाई के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। टीएमसी की गतिविधियां असहिष्णुता से भरी हुई हैं। उसके मुकाबले के लिए हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने को तैयार हैं। मैं अब दक्षिण २४ परगना जाऊंगा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलूंगा, जिनकी हिंसा में जान गई है।' जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय और भूपेंद्र यादव भी बंगाल पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो हुआ है, उन घटनाओं से हम चिंतित हैं और सदमे में हैं। मैंने ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के दौरान ही सुनी थीं। आजाद भारत में चुनाव नतीजों के बाद हमने कभी इस तरह की हिंसा नहीं देखी। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बातचीत कर चिंता जताई है। यही नहीं बीजेपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल कर हिंसा की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल की है। गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की है कि चुनाव के बाद हुई भीषण हिंसा की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब करे कि आखिर चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा को रोकने के लिए उसकी ओर से क्या कदम उठाए गए हैं। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ता की पत्नी शेफाली दास ने कहा है कि दक्षिण २४ परगना के कई इलाकों में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की है। शेफाली दास ने कहा, '२ मई को टीएमसी के गुंडों ने मेरे घर पर हमला क्या था क्योंकि मेरे पति बीजेपी के पोलिंग एजेंट थे। यहां तक कि उन्होंने हमें संपत्ति को बेचकर यहां से निकलने की धमकी दी है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने भी राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ से बात कर हिंसा पर चिंता जताई है। गवर्नर धनखड़ ने कहा, 'पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉल किया था और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्ति की।

सार समाचार

लोकतंत्र में हिंसा अस्वीकार्य, स्थिति पर नियंत्रण करें ममता : कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा की निंदा करते हुए मंगलवार को कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र में अस्वीकार्य हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को स्थिति पर नियंत्रण करना चाहिए। पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी जितिन प्रसाद ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने हमला किया है तथा महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। उन्होंने ट्वीट किया, ''चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई हिंसा अस्वीकार्य है। महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के जोगों ने इस अराजकता के लिए वोट नहीं दिया है।'' पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसी घटनाओं की निंदा करती है। उन्होंने कहा, ''कांग्रेस ने इस तरह की हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है।'' गोहिल ने कहा, ''ममता बनर्जी को इतना ज्यादा प्रेम और वोट मिला है। उन्हें हिंसा पर नियंत्रण करना चाहिए।'' .कांग्रेस नेता ने कहा, ''अगर हिंसा में मारे गए लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो भी हम उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं।

राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देगी दिल्ली सरकार, ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए वित्तीय मदद का ऐलान

नयी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार अगले दो महीने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 72 लाख राशन कार्डधारकों को मुफ्त राशन तथा ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका यह मतलब नहीं है कि संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन दो महीने तक लागू रहेगा। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली में हालात सुधरेंगे और लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान 1.56 लाख ऑटो और टैक्सी चालकों में से प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी थी और इस बार भी उनकी मदद करेगी। कोविड-19 के मामलों में लगातार तेज बढ़ोतरी के कारण 10 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन लागू है।

प्रधानमंत्री के नये घर की बजाय लोगों की जान बचाने के लिए लगाया जाए संसाधन : प्रियंका गांधी

नयी दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री के लिए नया घर बनाने की बजाय लोगों की जान बचाने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, ''जब देश के लोग ऑक्सीजन, वैक्सीन, हॉस्पिटल बेड, दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं तब सरकार 13000 करोड़ से प्रधानमंत्री का नया घर बनवाने की बजाए सारे संसाधन लोगों की जान बचाने के काम में डाले तो बेहतर होगा।'' प्रियंका ने कहा कि इस तरह के खर्चों से जनता को यह संदेश जाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं किसी और दिशा में हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति को बताया कि महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत प्रधानमंत्री आवास का निर्माण दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। समिति ने परियोजना के लिये अपनी मंजूरी दी है। इस परियोजना को विकसित कर रहे सीपीडब्ल्यूडी ने विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) को सूचित किया कि संसद की इमारत के विस्तार और संसद की नई इमारत का निर्माण नवंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा और प्रधानमंत्री आवास का निर्माण 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।

AAP नेता संजय सिंह का दावा, विधानसभा चुनाव में ढह जाएगा भाजपा का किला

लखनऊ। आम आदमी पार्टी (आप) ने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव नतीजों को दिल्ली के केजरीवाल मॉडल पर सूबे की जनता की मुहर करार देते हुए मंगलवार को दावा किया कि राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा का किला ढहने वाला है। आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने यहां एक बयान में कहा कि जनता ने पंचायत चुनाव में केजरीवाल के विकास मॉडल को स्वीकारते हुए आम आदमी पार्टी को भरपूर प्यार दिया है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सत्ताधारी भाजपा को जन विरोधी नीतियों का जवाब अपने वोट से देकर यह बता दिया है कि योगी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।

अशोक गहलोत की अपील, कोरोना प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करें लोग

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को लोगों से कहा कि वह कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करेंगे तभी कोरोना संक्रमण की कड़ी टूटेगी और संक्रमितों की बढ़ती संख्या पर विराम लगेगा। गहलोत ने ट्वीट किया, संक्रमितों की चेन तोड़ना आमजन द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने से ही सम्भव होगा जिससे अविलम्ब संख्या में ब्रेक लगेगा अन्यथा स्थिति और भयावह बन सकती है।

हैदराबाद में 8 एशियाई शेरों को हुआ कोरोना, चिड़ियाघरों और नेशनल पार्क्स को बंद करने का आदेश

नागपुर। (एजेंसी)।

बीते कई दिनों से देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। अब तक देश में कोविड की वजह से दो लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि, अभी तक यह वायरस सिर्फ इंसानों में ही पाया जा रहा था, लेकिन हैदराबाद में एशियाई शेरों में संक्रमण मिला है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क (एनजेडपी) में आठ एशियाई शेर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि, ये सभी शेरों की तबीयत ठीक है और धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं। जानवरों में कोविड-19 होने का देश में यह संभवतः पहला मामला है। इन शेरों की पिछले महीने आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट में ये संक्रमित निकले हैं। वहीं, शेरों के कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद देशभर के चिड़ियाघरों और नेशनल पार्क्स को बंद करने का निर्देश दिया गया है।

29 अप्रैल को सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलेक्यूलर बायोलॉजी ने एनजेडबी के अधिकारियों को बताया था कि ये शेर पॉजिटिव हैं। एनजेडपी के डॉ. सिद्धानंद कुकरेती ने रिपोर्ट को कंफर्म करते हुए बताया कि अब शेर बेहतर हो रहे हैं। पिछले साल अप्रैल महीने में न्यूयॉर्क के ब्रॉनोक्स जू में आठ बाघ कोविड से संक्रमित मिले थे, लेकिन इस बार पहली बार यह देश में शेरों में मामला सामने आया है। वाइल्डलाइफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर डॉ. शिरीष उपाध्याय ने बताया कि ब्रॉनोक्स में सामने आए मामले के बाद कहीं पर भी वाइल्ड एनिमिल्स में कोविड पॉजिटिव होने का मामला सामने नहीं आया था। हालांकि, हॉन्ग-कॉन्ग में कुत्तों और बिल्लियों में जरूर वायरस मिल चुका है।

पिछले महीने 24 तारीख को जब डॉक्टर पार्क का दौरा कर रहे थे, तभी उन्हें दिखाई दिया कि कुछ शेरों के नाक से पानी आ रहा है और कफ कर रहे हैं। साथ ही कुछ खाना भी नहीं खा रहे थे। इसके बाद उन्होंने इन शेरों के स्वैब सैंपल्स लिए और फिर जांच करने के लिए भेजा गया। बाद में पार्क के आठ शेर कोविड से संक्रमित मिले। पॉजिटिव पाए जाने की वजह से इन शेरों को आइसोलेट कर दिया गया है और जरूरी इलाज दिया जा रहा है। सभी इलाज से लगातार बेहतर हो रहे हैं। टेस्टिंग से पता चला है कि यह संक्रमण किसी गंभीर वेरिएंट की वजह से नहीं हुआ था। वहीं, अभी तक इस बात का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं मिला है कि यह बीमारी किसी जानवर से इंसान तक पहुंच सकती है।

हिंसा पर सक्रिय हुआ चुनाव आयोग : नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर मिली सुरक्षा, बंगाल जाएगी महिला आयोग की टीम

नई दिल्ली / कोलकाता (एजेंसी)।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से जारी हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः लिया है। यही नहीं महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के नेतृत्व में एक टीम बंगाल का दौरान करने वाली है। आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए टीम दौरा करेगी। महिला आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'नंदीग्राम में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने जांच की मांग की है। डीजीपी को भेजे लेटर में आयोग की मुखिया रेखा शर्मा ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आरोपियों पर तत्काल एक्शन लिए जाने की मांग की है।'

महिला आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'ट्विटर पर आयोग ने ऐसी कई पोस्ट देखी हैं, जिनमें नंदीग्राम में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जा रही है। ऐसी तस्वीरों से महिला आयोग आहत हुआ है। इससे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ है। आयोग की मुखिया रेखा शर्मा ने राज्य के डीजीपी को खत लिखकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आरोपियों पर तत्काल एक्शन लेने की मांग की है। इन घटनाओं की समयबद्ध जांच कराने की भी मांग की है। इसके अलावा मामले की जांच के लिए अध्यक्षा रेखा शर्मा की लीडरशिप में एक टीम भी बंगाल का दौरा करने वाली है।'

यही नहीं नंदीग्राम में रिटर्निंग ऑफिसर रहे अधिकारी को राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा प्रदान की गई है। सरकार ने चुनाव आयोग को यह जानकारी दी है। आयोग ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार से कहा था कि वह नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर को पर्याप्त सुरक्षा कवर मुहैया कराए। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंच गए हैं। राज्य में पहुंचते ही उन्होंने हिंसा का शिकार हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाकर मुलाकात की है। यही नहीं वह हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से भी मुलाकात करने वाले हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचते ही नड्डा ने कहा कि राज्य में हिंसा और आतंक का माहौल है।

उन्होंने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो हुआ है, उन घटनाओं से हम चिंतित हैं और सदमे में हैं। मैंने ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के दौरान ही सुनी थीं। आजाद भारत में चुनाव नतीजों के बाद हमने कभी इस तरह की हिंसा नहीं देखी। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बातचीत कर चिंता जताई है। यही नहीं बीजेपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल कर हिंसा की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल की है।

ग्रामीण इलाकों में जानलेवा साबित हो रहा है संक्रमण को लेकर सरकार का झूठ : अखिलेश

लखनऊ। (एजेंसी)।

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का 'झूठ' गांव देहात के इलाकों में बेहद जानलेवा साबित हो रहा है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश के गाँव-गाँव तक कोरोना वायरस संक्रमण का फैलना बहुत चिंताजनक है। गाँव-तहसील में जब बुख़ार की दवाइयों तक की भारी किल्लत है तो ऑक्सीजन, बेड या टीके की क्या उम्मीद की जाए।

सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया, भाजपा सरकार का ये झूठ कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण न के बराबर है, ग्रामीण इलाक़ों में बेहद जानलेवा साबित हो रहा है। गौरतलब है कि ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने पांच मई से इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाने का फैसला किया है।

ग्वालियर स्मार्ट सिटी की अनूठी पहल योजनाबद्ध तरीक़े से सुनिश्चित की जा रहीं ऑक्सीजन सप्लाई

ग्वालियर। (एजेंसी)।

कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने समूचे देश को अपनी चपेट में ले रखा है। इस बार संक्रमण की रफ़्तार भी तेज है व इसका असर भी संक्रमित व्यक्ति के स्वास्थ्य पर ज़्यादा है। परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के अनुपात में इस वर्ष अधिक रोगी अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं व उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। इस बढ़ी डिमाण्ड की पूर्ति एक बड़ी चुनौती है तथा इसे सुनिश्चित करने हेतु स्मार्ट सिटी द्वारा व्यापक कार्ययोजना बनाई गई है। इस प्रक्रिया में ज़िला प्रशासन की टीम से समन्वय स्थापित कर ऑक्सीजन सिलेंडर 70 से ज़्यादा अस्पतालों तक आँकलन के अनुसार पहुँचाये जा रहे हैं।

जानिये कैसे काम कर रहा है यह सिस्टम : ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु एक टास्क फ़ोर्स का गठन किया गया है जिसमें 30 पटवारी, 1 नायब तहसीलदार व 1 एसडीएम को शामिल किया गया है। पटवारियों को अस्पताल निर्धारित किये गए हैं जहां की रियल टाइम स्थिति से कमांड सेंटर की टीम को अवगत कराया जाता है। यह टीम 24ङ्ग7 कार्यरत रहती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने पर कमांड सेंटर द्वारा इमर्जेन्सी स्टॉक अथवा रीफ़िल स्टेशन से त्वरित कार्यवाही कर सिलेंडर वितरण सुनिश्चित किया जाता है। इस पूरे क्रम पर स्मार्ट सिटी सीईओ श्रीमती जयति सिंह निरन्तर नज़र बनाये रहती हैं तथा रियल टाइम रेस्पॉन्स सुनिश्चित करती हैं। जानकारी देते हुये श्रीमती सिंह ने बताया की ग्वालियर स्मार्ट सिटी तथा ज़िला प्रशासन के समन्वय से ऑक्सीजन वितरण को एक योजनाबद्ध तरीक़े से किया जा रहा है।

पिछले हफ्ते जब ऑक्सीजन की कमी के चलते पैनिक कॉल आने शुरू हुये तो स्मार्ट सिटी ने सभी अस्पतालों व वहाँ भर्ती मरीज़ों के डेटा को कम्पाइल कर माँग का आँकलन किया और चरणबद्ध योजना बनाई। हर दो घंटे में सभी 70 अस्पताल की माँग व आपूर्ति का पुनः आँकलन किया जाता है तथा इसके अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों तक पहुँचाये जा रहे हैं। ग्वालियर स्मार्ट सिटी की टीम संक्रमित के परिजनों, अस्पताल, फ़िलिंग स्टेशन-तीनों के बीच तालमेल बैठा मदद पहुँचा रही है तथा इस समन्वय से रियल टाइम में ऐक्शन सम्भव होता है। आज की परिस्थिति में समय रहते सहायता पहुँचाना अहम है तथा विलम्ब का विकल्प मौजूद नहीं है। इसीलिए स्मार्ट सिटी की भूमिका और भी अहम हो जाती है।

आपात स्थिति के लिए बनाया बफ़र स्टॉक : ऑक्सीजन की कमी होते ही संक्रमितों के परिजन कमांड सेंटर पर कॉल करते हैं तथा ऑक्सीजन अथवा शिफ़्टिंग करने का आग्रह करते हैं। इस स्थिति को देखते हुये स्मार्ट सिटी ने ज़िला प्रशासन व पुलिस के साथ एक बफ़र स्टॉक का प्रावधान किया है जिससे आपात स्थिति से तत्काल निपटा जा सकेगा।

पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के लिए भाजपा का अहंकार भी जिम्मेदार : शिवसेना

मुंबई। (एजेंसी)।

शिवसेना ने मंगलवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के कारणों में भाजपा का ''अहंकार'' भी शामिल है। शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में कहा गया है कि महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर रहने के लिए भाजपा की ''असहिष्णुता'' जिम्मेदार थी। यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आयी है जब कुछ दिन पहले महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के मंत्री छगन भुजबल को भाजपा के बारे में बोलने के दौरान संभलकर शब्दों का इस्तेमाल करने को कहा था। भुजबल ने पश्चिम बंगाल चुनाव के संदर्भ में भाजपा के बारे में कुछ टिप्पणी की थी। संपादकीय में सवाल किया गया, ''महाराष्ट्र कब इतना असहिष्णु हो गया?'' 'सामना' में कहा गया, ''पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हार के लिए भाजपा का 'अहंकार' भी जिम्मेदार है।''

शिवसेना ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हार के कारण भाजपा महाराष्ट्र में पंढरपुर सीट पर उपचुनाव में जीत का जश्न भी नहीं मना पा रही। महाराष्ट्र में विधानसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ एमवीए को झटका लगा है। भाजपा उम्मीदवार समाधान आवताडे ने सोलापुर में पंढरपुर-मंगलवेधा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में राकांपा उम्मीदवार को 3700 से ज्यादा मतों से हरा दिया। संपादकीय में कहा, ''महाराष्ट्र विकास आघाडी (एमवीए) को पंढरपुर उपचुनाव में हार मिली और हर किसी ने भाजपा और जीतने वाले उम्मीदवार को बधाई दी। लेकिन विजेता को बधाई देने वाले को एमवीए के किसी भी नेता ने धमकी नहीं दी।

कांग्रेस ने कोरोना को लेकर सर्वदलीय बैठक की मांग की, सेंट्रल विस्टा पर सवाल उठाया

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

कांग्रेस ने देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। पार्टी ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार ऑक्सीजन, वेंटिलेंटर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता पर ध्यान देने की बजाय सेंट्रल विस्टा परियोजना और प्रधानमंत्री का नया आवास बनाने में हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ''सेंट्रल विस्टा पर 13450 करोड़ रुपये या फिर 45 करोड़ भारतीय नागरिकों को टीका लगाने के लिए खर्च हो या एक करोड़ ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जाएं या दो करोड़ भारतीय परिवारों को 'न्याय' के तहत छह हजार रुपये दिए जाएं। प्रधानमंत्री का अहंकार लोगों के जीवन से बड़ा है।''

पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने संवाददाताओं से कहा, ''कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत के समय इस देश के सुल्तान ने देशवासियों को राम के भरोसे छोड़ दिया है। पूरा देश आज अपनी जान बचाने के लिए सरकार की ओर नहीं देख सकता है, सरकार के अस्पताल की ओर नहीं देख सकता। अब लोगों को कह दिया गया कि आत्मनिर्भरता से मरो।'' उन्होंने कहा, ''देश को जरुरत थी कि युद्ध स्तर पर काम हो। स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी अवसरंजना का विस्तार करना चाहिए। ऑक्सीजन और रेमेडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। दवाइयां मिलनी चाहिए, वेंटिलेटर वाले बेड मिलने चाहिए और आईसीयू वाले बेड मिलने चाहिए। आज देश को इनकी जरुरत है।''

उन्होंने दावा किया, ''आज की जरूरतों को ध्यान नहीं देकर देश के सुल्तान ने अपना नया आवास बनाने की घोषणा की है। जब लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, तब इस देश की सरकार सुल्तान का महल बनाने जा रही है। क्या ये प्राथमिकता होनी चाहिए?'' गोहिल ने कहा, ''किसी सुल्तान की सुल्तानगिरी नहीं चल सकती है। यह देश लोकतंत्र के साथ चलता है। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और सेंट्रल विस्टा पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं किये जाएं।'' उन्होंने कहा कि सरकार को सभी लोगों के साथ मिलकर कोरोना से निपटने का प्रयास करना चाहिए।

ऑक्सीजन आपूर्ति पर कोर्ट ने केंद्र से कहा- आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा सकते हैं, हम नहीं

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र से कारण बताने को कहा कि कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर आदेश की तामील नहीं कर पाने के लिए उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए। अदालत ने कहा, ''आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा सकते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या आपको इन चीजों के बारे में पता नहीं है।'' न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्र की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि मौजदा चिकित्सकीय ढांचे के आलोक में दिल्ली 700 मीट्रिक टन चिकित्सकीय ऑक्सीजन की हकदार नहीं है। पीठ ने कहा, ''हम हर दिन इस खौफनाक हकीकत को देख रहे हैं कि लोगों को अस्पतालों में ऑक्सीजन या आईसीयू बेड नहीं मिल रहे, कम गैस आपूर्ति के कारण बेड की संख्या घटा दी गयी है।'' अदालत ने केंद्र सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस पर जवाब देने के लिए बुधवार को अदालत के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का 30 अप्रैल का विस्तृत आदेश दिखाता है कि उसने केंद्र को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराने का निर्देश दिया था ना कि महज 490 मीट्रिक टन। पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय पहले ही आदेश दे चुका है, अब उच्च न्यायालय भी कह रहा है कि जैसे भी हो केंद्र को हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी होगी।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)